[2024] 6 एस. सी. आर 530:2024 आई. एन. एस. सी. 381

अभिमीत सिन्हा और अन्य

बनाम

पटना उच्च न्यायालय और अन्य

(2016 की रिट याचिका (सी) संख्या 251)

06 मई 2024

[ऋषिकेश रॉय* और प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्तिगण]

<u>विचार के लिए मुद्दा</u>

बिहार उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1951 और गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2005 की संवैधानिकता के संबंध में मुद्दा उठा, जिसमें क्रमशः बिहार और गुजरात राज्यों में जिला न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए चयन मानदंड के एक हिस्से के रूप में वाइवा वॉस टेस्ट में न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए गए हैं; क्या वाइवा वॉस के लिए न्यूनतम अंकों का निर्धारण, इस न्यायालय द्वारा अखिल भारतीय न्यायाधीशों (2002) में निर्धारित कानून के उल्लंघन में है, जिसने शेट्टी आयोग की कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया है; क्या वाइवा वॉस के लिए न्यूनतम अंकों का निर्धारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। ; क्या बिहार में चयन प्रक्रिया अंकों के संयम और सुधारात्मक कदमों को देखते हुए दूषित हुई है; क्या संविधान के अनुच्छेद 234 के तहत आवश्यक लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श किए बिना। गुजरात राज्य में सिविल न्यायाधीश के पद पर चयन गुजरात नियम, 2005 (2011 में संशोधित) को अमान्य कर देगी।

हेडनोट्स

न्यायपालिका-न्यायिक अधिकारियों का चयन-बिहार राज्य के लिए बार (2015 विज्ञापन) से सीधी भर्ती द्वारा जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) और गुजरात राज्य के लिए सिविल न्यायाधीश (2019 और 2022 विज्ञापन) का पद-गुजरात नियम, 2005 का नियम 8 (5) और बिहार नियम का खंड 11 नियुक्ति के लिए चयन मानदंड के एक भाग के रूप में मौखिक परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करता है, यदि इस न्यायालय द्वारा * अखिल भारतीय न्यायाधीश (2002) मामले में निर्धारित कानून का उल्लंघन किया जाता है, जिसने शेट्टी आयोग की कुछ सिफारिशों को स्वीकार कियाः

अभिनिर्धारित किया गयाः साक्षात्कार के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों का निर्धारण अनुमत है-यह अखिल भारतीय न्यायाधीशों (2002) मामले का उल्लंघन नहीं है जिसने शेट्टी आयोग की कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया-अखिल भारतीय न्यायाधीशों (2002) मामले में निर्णय उप-साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों के पहलू पर मौन-इसे साक्षात्कार खंड में न्यूनतम कट-ऑफ अंकों को समाप्त करने पर आधिकारिक रूप से घोषित किए जाने के रूप में नहीं माना जा सकता है-शेट्टी आयोग की सिफारिशों और नियमों के बीच विसंगति के मामले में, मौजूदा वैधानिक नियमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए-मौजूदा नियमों के अभाव में, उच्च न्यायालय को इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करना चाहिए-इसके अलावा, भले ही वैधानिक नियमों को अंतराल को भरने के लिए पूरक किया जा सकता है, उच्च न्यायालय नियमों के विपरीत कार्य नहीं कर सकता है-भर्ती प्रक्रिया में न्यूनतम कट-ऑफ का निर्धारण उम्मीदवारों की जानकारी के लिए शुरू होने से पहले ही अधिसूचित किया गया था पटना उच्च न्यायालय के तहत चयन प्रक्रिया-अखिल भारतीय न्यायाधीशों (2002) में निर्णय के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि सर्वोत्तम संभव व्यक्ति का चयन सुनिश्चित करने के लिए साक्षात्कार खंड में योग्यता अंक निर्धारित करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं थी-इस प्रकार, नियमों में न्यूनतम अंकों का निर्धारण अखिल भारतीय न्यायाधीशों (2002)-

बिहार सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 1951-गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2005 में निर्णय के उल्लंघन में नहीं पाया गया है। [पैरा 102,37,39,40,48,49]

न्यायपालिका-न्यायिक अधिकारियों का चयन-गुजरात नियम, 2005 का नियम 8 (5) और बिहार नियम का खंड 11, यदि अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है, तो नियुक्ति के लिए चयन मानदंड के एक भाग के रूप में मौखिक परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करता हैः

अभिनिर्धारित किया गयाः बिहार नियम, 1951 और धाराओं के खंड 11 को वैधता चुनौती। 8(3) गुजरात नियम, 2005 (2011 में संशोधित) के अनुसार साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए जाते हैं-भर्ती प्रक्रिया में न केवल उम्मीदवार की बुद्धि की परीक्षा होनी चाहिए, बल्कि उच्च न्यायपालिका में पदों पर नियुक्ति के लिए उनके व्यक्तित्व की भी परीक्षा होनी चाहिए-न्यायिक रिक्तियों के लिए भर्ती में मौखिक साक्षात्कार न्यायिक पदों के लिए उम्मीदवार के व्यक्तित्व और क्षमता की परीक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं-लिखित परीक्षा के लिए उच्च अंक अपने आप में एक उम्मीदवार की योग्यता और उपयुक्तता का निर्धारण नहीं करते हैं-एक साक्षात्कार हाशिए पर पड़े उम्मीदवारों को अपनी प्रतिभा को उन तरीकों से प्रदर्शित करने का माध्यम भी प्रदान कर सकता है जो एक लिखित परीक्षा संभवतः अनुमति नहीं दे सकती है-साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य प्रदान कर सकते हैं एक वंचित पृष्ठभूमि से आने वालों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान एक समान अवसर, साक्षात्कारकर्ताओं की वास्तविक योग्यता और क्षमता का आकलन करने के लिए-समाधान साक्षात्कार करने वाले सदस्यों के साक्षात्कार की प्रक्रिया में पूर्वाग्रह को कम करने के लिए जागरूक और संवेदनशील होने में निहित है-हालाँकि, पूर्वाग्रह की आशंका को रद्द करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती है। नियम-वाइवा वॉस सेगमेंट के लिए ओवरराइडिंग वेटेज को अस्वीकार कर दिया गया है, लेकिन उचित योग्यता कट-ऑफ अंकों के निर्धारण को भेदभावपूर्ण नहीं माना जाता है-बिहार भर्ती के लिए 20 प्रतिशत और गुजरात भर्ती के लिए

40 प्रतिशत की न्यूनतम कट-ऑफ को उच्च सीमा प्रदान करने के लिए नहीं माना जा सकता है यदि कोई यह ध्यान रखता है कि भर्ती न्यायिक अधिकारियों के चयन के लिए है-इस प्रकार, संबंधित भर्ती नियम असंवैधानिक नहीं हैं-रिट याचिकाकर्ताओं की वैध अपेक्षा का कोई उल्लंघन नहीं है ताकि परीक्षा में विफल हो जाए। अनुच्छेद 14-बिहार सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 1951-गुजरात राज्य न्यायिक सेवा सेवा नियम, 2005। [पैरा 102,57,60,63,65,66,68]

न्यायपालिका-न्यायिक अधिकारियों का चयन-बिहार राज्य के लिए बार से सीधी भर्ती द्वारा जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) और बिहार में सिविल न्यायाधीश के पद पर भर्ती। गुजरात राज्य-न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने वाले नियम चयन मानदंड के एक भाग के रूप में वाइवा वॉयस टेस्ट में अंक नियुक्ति के लिए-चयन प्रक्रिया, यदि दूषित हो जाती है तो अंकों को कम करना और सुधारात्मक कदमः

अभिनिर्धारित किया गयाः बिहार राज्य में चयन प्रक्रिया कानूनी रूप से वैध पाई गई और इसे बरकरार रखा गया-परीक्षा आयोजित करने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए बाद के कदमों की जांच करने पर, बिहार में पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित करने के लिए कोई दुर्भावनापूर्ण या वैधानिक उल्लंघन नहीं पाया गया-उच्च न्यायालय को न्यायपालिका के हित में स्पष्टीकरण, छूट और यहां तक कि छूट प्रदान करने के लिए आवश्यक शक्तियां निहित की गई थीं-शब्दों में "छूट" के साथ-साथ किसी भी "कठिनाई" के मामले में आदेश/निर्देश जारी करने की सामान्य शक्ति, साक्षात्कार परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को प्रदान करने के लिए संयम की प्रक्रिया की अनुमति देगी-एक संयम अभ्यास में, अतिरिक्त अंकों की संख्या और/या अंकों की कटौती की परिकल्पना की गई है-यदि चयन प्रक्रिया में कुछ हल करने योग्य कमियां देखी जाती हैं, तो उच्च न्यायालय के पास सुधारात्मक उपाय करने की गुंजाइश है-संयम की प्रक्रिया का हमेशा ईमानदारी से उपयोग किया जा सकता है यदि यह सभी उम्मीदवारों को समान रूप से लाभान्वित करता है-यह नहीं कहा जा सकता है

कि सुधारात्मक उपाय प्रामाणिक नहीं थे-अपनाई गई प्रक्रिया नियमों के अनुरूप है-प्रस्तुत चार्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि संयम, वास्तव में, रिट याचिकाकर्ताओं को साक्षात्कार दौर में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए लाभान्वित करता है-चयन समिति के निर्णय को पूर्ण न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय के लिए उपलब्ध उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुमोदित किया गया था। चयन-जहां तक गुजरात के मामलों का संबंध है, अस्पष्ट आरोप लगाने के अलावा, चयन समिति की ओर से [2024] 6 एस. सी. आर. में किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे या पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्षात्कार प्रक्रिया-इस प्रकार, चयन प्रक्रिया दूषित नहीं पाई गई-बिहार सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 1951-गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2005। [पैरा 102,80,75,76,78,79]

भारत का संविधान-अनुछेद 234-न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति-गुजरात राज्य में सिविल न्यायाधीश के पद के लिए चयन-चयन नियम-गुजरात नियम, 2005 (2011 में संशोधित) में संशोधन के लिए लोक सेवा आयोग के साथ गैर-परामर्श, यदि शून्य हो जाता है, तो न्यूनतम वाइवा वॉस अंक निर्धारित करनाः

अभिनिर्धारित किया गयाः लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श न करने से गुजरात नियम, 2005 (2011 में संशोधित) अमान्य नहीं हो जाएगा-गुजरात में, जब लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 320 (3) के प्रावधान के तहत परामर्श नहीं करना चाहता था, इस तरह के परामर्श के अभाव में, यह नहीं माना जा सकता है कि गुजरात नियम, 2005 किसी भी कानूनी या संवैधानिक अयोग्यता से ग्रस्त है, विशेष रूप से जब नियम उच्च न्यायालय के साथ उचित परामर्श के साथ बनाए गए थे-अनुच्छेद 234 में परिकल्पित उच्च न्यायालय के साथ परामर्श न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने के लिए है-उच्च न्यायालय के साथ परामर्श को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की तुलना में न्यायिक भर्ती के मामलों में-यदि आयोग परामर्श नहीं लेना चाहता है तो राज्यपाल

को लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की कोई बाध्यता नहीं है-इस प्रकार, गुजरात नियमों को इस मामले में शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है-संवैधानिक योजना में एक संस्थान के रूप में उच्च न्यायालय को जो दर्जा प्राप्त है और उसके पास न्यायिक सेवाओं की विशेषज्ञता और अनुभव है, वह परामर्श की प्रक्रिया में उच्च न्यायालय को सौंपे गए प्रमुख स्थान को उचित ठहराता है-इस प्रकार, नियम बनाने के लिए उच्च न्यायालय से परामर्श करना अनिवार्य है और इस तरह के परामर्श के बिना राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित कोई भी नियम अधिकार से बाहर है। [पैरा 102,97,87,93,96]

न्यायपालिका-न्यायिक अधिकारियों की भर्ती/चयन-न्यायिक सेवा परीक्षाओं के संचालन के संबंध में कुछ निर्देश/सुझावः

अभिनिर्धारित किया गयाः पारदर्शिता सुनिश्चित करने और चयन प्रक्रिया में दुविधाओं से बचने के लिए नियमों में मॉडरेशन जैसी प्रक्रियाओं को अधिमानतः निर्धारित किया जाना चाहिए-साक्षात्कार खंड में विचार के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, जब प्राधिकरण को ऐसा करने की आवश्यकता हो तो वास्तविक कारणों के लिए अंकों के मॉडरेशन की अनुमति दी जानी चाहिए-इसके अलावा, एक निर्दिष्ट प्राधिकारी की अनुपस्थिति है जिससे उम्मीदवारों द्वारा संपर्क किया जा सकता है-स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं, कार्यों और जिम्मेदारियों के साथ दी गई भर्ती प्रक्रिया के लिए एक निर्दिष्ट प्राधिकारी को अधिसूचित करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालय-उम्मीदवार किसी भी संदेह के मामले में स्पष्टीकरण लेने के लिए ऐसे निर्दिष्ट प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और इससे उम्मीदवारों की चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी-साक्षात्कार पैनल में उन लोगों का पदनाम, नियमों में उचित रूप से प्रदान किया जाए-प्रस्तावित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम की बुनियादी रूपरेखा प्रदान की जाए, ताकि विभिन्न पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को परीक्षा अधिसूचना जारी होने से पहले ही प्रस्तावित परीक्षा की योजना बनाने और तैयारी करने में मदद मिल सके-साथ ही भर्ती प्रक्रिया भी। समय सीमा

का पालन करना चाहिए लेकिन यदि कोई विशेष और अपरिहार्य आवश्यकता है, तो हितधारकों को उचित शीघ्रता के साथ सूचित किया जाना चाहिए-कहा गया निर्णय भारत के सभी उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायाधीशों के ध्यान में लाया जाना चाहिए ताकि सभी हितधारकों को परिणामी कदम उठाने में सक्षम बनाया जा सके। [पैरा 100,101]

भारत का संविधान-अनुच्छेद 32-रिट याचिका-रखरखाव - बहिष्करण का सिद्धांत-प्रयोज्यता-बिहार और गुजरात राज्यों में जिला न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए चयन मानदंड के एक भाग के रूप में मौखिक परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंकों को निर्धारित करने वाले नियमों की संवैधानिकता से संबंधित मामला-विभिन्न उच्च न्यायालयों की याचिका कि भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के बाद, रिट याचिकाकर्ता सफल नहीं हो सकते हैं, भर्ती प्रक्रिया या भर्ती नियमों के अधिकारों को चुनौती नहीं दे सकते हैं; कि सभी उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम अंकों के निर्धारण के बारे में पता था, चयन प्रक्रिया शुरू होने से बहुत पहले और मौखिक परीक्षा का सिद्धांत असफल चुनौती देने वालों के खिलाफ काम करेगा। रिट याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि चयन प्रक्रिया में स्पष्ट अवैधताओं के कारण एस्टोपेल सिद्धांत लागू नहीं होता है; और यह कि एस्टोपेल तब लागू नहीं होती है जब निरंकुशता अनुच्छेद 14 और 16 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है।

अभिनिर्धारित किया गयाः एस्टोपेल कानून पर हावी नहीं हो सकता है-इस तरह के मामलों में, शुरआत में ही रिट याचिकाकर्ताओं का मुकदमा न लेना बिल्कुल अनुचित होगा जब प्रक्रिया में कथित कमियों का अनुमान केवल चयन प्रक्रिया में भागीदारी से लगाया जा सकता है। [पैरा 19-20]

भारत का संविधान-अनुच्छेद 32-पूर्व न्याय (रेख ज्यूडीकाटा) का सिद्धांत - वाइवा वॉयस टेस्ट में न्यूनतम योग्यता अंकों के रूप में निर्धारित करने वाले नियमों की संवैधानिकता के संबंध में तत्काल मामला। क्रमशः बिहार और गुजरात राज्यों में जिला न्यायपालिका में

नियुक्ति के लिए चयन मानदंड का एक हिस्सा- नियम की वैधता। 8(3) गुजरात नियम, 2005 (संशोधित के रूप में) को पहले उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, और इस न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय ने साक्षात्कार के लिए 40 प्रतिशत कटऑफ अंक निर्धारित करने वाले संशोधन की वैधता को बरकरार रखा, और इसके खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को फिर से खारिज कर दिया गया-पूर्व न्याय का सिद्धांत, यदि आकर्षित किया जाता हैः

अभिनिर्धारित किया गयाः हालाँकि, पूर्व न्याय के सिद्धांत को सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है-यह वही रिट याचिकाकर्ता नहीं था जिसने अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था-यहां न्यायालय का सामना तथ्यों के एक अलग समूह से होता है, वादियों के एक अन्य समूह ने अतिरिक्त तर्क उठाए हैं-इस प्रकार, यह निवेदन कि रिट याचिका को पूर्व न्याय के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए, उचित है-किसी भी मामले में, विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने का कानून के प्रश्न पर कोई परिणाम नहीं है। [पैरा 23]

न्यायपालिका-न्यायिक अधिकारियों का चयन- अखिल भारतीय न्यायाधीश (2002) मामला जिसने शेट्टी आयोग की कुछ सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कुछ को संशोधित या अस्वीकार कर दिया। अन्य-समझाया गया। [पैरा 33,34,36,37,49]

न्यायपालिका-न्यायिक अधिकारियों का चयन-शेट्टी आयोग की सिफारिशें-उत्पत्ति-न्यायपालिका का स्पष्टीकरण। [पैरा 25-32]

न्यायपालिका-न्यायिक अधिकारियों का चयन-शेट्टी आयोग की सिफारिशें-इनका कार्यान्वयनः

अभिनिर्धारित किया गयाः तथ्यों की बात करें तो संशोधित नियमों के अनुसार न्यूनतम कट-ऑफ 55 प्रतिशत थी और इसे बिहार नियम, 1951 के खंड 10 के प्रावधान के अनुसार घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था-वाइवा वॉस खंड में कट-ऑफ अंकों को समाप्त करने

के लिए शेट्टी आयोग की सिफारिशों का चयनात्मक कार्यान्वयन नहीं किया जा सकता है-उम्मीदवारों को एक ही बार में "अनुमोदन और खंडन" करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-शेट्टी आयोग द्वारा अनुशंसित मानदंडों को कम करने की मांग करना अस्वीकार्य होगा, केवल वाइवा वॉस खंड के लिए-शेट्टी आयोग ने सिफारिश की कि व्यक्तिपरकता और मनमानेपन की डिग्री को कम किया जाना चाहिए और चयन किया जाना चाहिए। पारदर्शी होना चाहिए। [पैरा 30,31]

गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2005 -आर. 8 (5)-वाइवा वॉयस-ऑब्जेक्ट-एक्सप्लेनड। [पैरा 67]

<u>मामला कानून उद्धृत किया गया</u>

*अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम संघ भारत और अन्य [2002] 2 एससीआर 712: **(2002) 4 एस. सी. सी. 247-समझाया और उस पर भरोसा किया।**

डॉ. (मेजर) मीता सहाय बनाम भारत संघ **(2019) 20 एस. सी. सी. 17-पर भरोसा किया।**

शिवानंद सी. टी. बनाम केरल उच्च न्यायालय [2023] 11 एस. सी. आर. 674: **(2024) 3 एस. सी. सी. 799; हेमानी मल्होत्रा बनाम हाई दिल्ली न्यायालय** [2008] 5 एस. सी. आर. 1066: **(2008) 7 एससीसी 11;** रमेश कुमार बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय [2010] 2 एससीआर 256 : **(2010) 3 एससीसी 104-विशिष्ट।**

ए. सी. थलवाल बनाम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय [2000] सप.2 एससीआर 428**: (2000) 7 एस. सी. सी. 1-लागू नहीं होता है।**

एन. देवासाहयम बनाम मद्रास राज्य, **आकाशवाणी (1958) मैड 53 - अस्वीकृत।**

राज कुमार बनाम शक्ति राज [1997] 1 एससीआर 1159: **(1997) 9 एस. सी. सी. 527;** बशेशर नाथ बनाम कम्र आय-कर, दिल्ली [1959] सप.1 एससीआर 528: **आकाशवाणी**

(1959) एस. सी. 149; ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम [1985] सप. 2 एससीआर 51: **आकाशवाणी (1986) एससी 180;** नर सिंह पाल बनाम भारत संघ और अन्य [2000] 2 एससीआर 752: **(2000) 3 एस. सी. सी. 588;** मदन लाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य [1995] 1 एस. सी. आर. 908: **(1995) 3 एस. सी. सी. 486;** धनंजय मलिक बनाम राज्य उत्तरांचल [2008] 3 एससीआर 1035: **(2008) 4 एससीसी 171;** रमेश चंद्र शाह बनाम अनिल जोशी [2013] 5 एससीआर 687: **(2013) 11 एस. सी. सी. 309;** अनुपल सिंह बनाम राज्य उत्तर प्रदेश [2019] 12 एससीआर 1071: **(2020) 2 एससीसी 173;** कृष्ण राय बनाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (2022) 7 एससीआर 1104: **(2022) 8 एस. सी. सी. 713;** दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1962] 1 एस. सी. आर. 574: **आकाशवाणी (1961) एससी 1457;** इंद्रजीत सिंह सोढ़ी बनाम अध्यक्ष, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड [2020] 11 एससीआर 966: **(2021) 1 एस. सी. सी. 198;** अखिल भारतीय न्यायाधीश एसोसिएशन बनाम भारत संघ [1991] सप. 2 एससीआर 206: **(1992) 1 एस. सी. सी. 119;** अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम संघ भारत का [1993] पूरक. 1 एससीआर 749: **(1993) 4 एससीसी 288;** प्रदीप कुमार राय बनाम दिनेश कुमार पांडे [2015] 6 एससीआर 825: **(2015) 11 एस. सी. सी. 493;** डॉ. कविता कंबोज बनाम पंजाब और हरियाणा और अन्य का उच्च न्यायालय [2024] 2 एससीआर 1136: **2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 254;** सैयद टी. ए. [2024] 6 एस सी आर। नक्शबंदी बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य [2003] सप. 1 एससीआर 114: **(2003) 9 एस. सी. सी. 592;** राखी रे बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय [2010] 2 एससीआर 239: **(2010) 2 एससीसी 637;** महिंदर कुमार बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय [2013] 13 एस. सी. आर. 884: **(2013) 11 एससीसी 87;** शशिधर रेड्डी बनाम राज्य एपी [2013] 12 एससीआर 985: **(2014) 2 एससीसी 158;** सलाम समरजीत सिंह बनाम इम्फाल में मणिपुर का उच्च न्यायालय [2016] 9 एससीआर 771: **(2016) 10 एस. सी. सी. 484;** शायरा बानो बनाम भारत संघ [2017] 9 एस. सी. आर.

797: **(2017) 9 एससीसी 1;** जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ [2018] 11 एससीआर 765: **(2019) 3 एससीसी 39;** लोक प्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2016 (4) एससीआर 1026: **(2016) 8 एससीसी 389;** ई. पी. रोयप्पा बनाम राज्य टी. एन. [1974] 2 एस. सी. आर. 328: **(1974) 4 एस. सी. सी. 3;** अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब सेहरावर्दी [1981] 2 एससीआर 79: **(1981) 1 एस. सी. सी. 722;** एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ [2024] 2 एस. सी. आर. 420: **2024 आई. एन. एस. सी 113;** लीला धर बनाम राजस्थान राज्य [1982] 1 एस. सी. आर. 320: **(1981) 4 एस. सी. सी. 159;** के. एच. सिराज बनाम केरल उच्च न्यायालय [2006] सप. 2 एससीआर 790: **(2006) 6 एससीसी 395;** राज्य उत्तर प्रदेश बनाम रफीक्विद्दीन [1988] 1 एस. सी. आर. 794: **(1987) पूरक एस. सी. सी. 410;** तानिया मलिक बनाम उच्च न्यायालय के महापंजीयक दिल्ली न्यायालय [2018] 10 एस. सी. आर. 348: **(2018) 14 एससीसी 129;** प्रणव वर्मा बनाम उच्च पंजीयक न्यायालय [2019] 15 एससीआर 43: **(2020) 15 एससीसी 377;** बी. के. पवित्रा बनाम भारत संघ [2017] 1 एस. सी. आर. 631: **(2019) 16 एस. सी. सी. 129;** मनीष कुमार शाही बनाम बिहार राज्य **(2010) 12 एस. सी. सी. 576;** अशोक कुमार यादव बनाम राज्य हरियाणा [1985] सप.1 एससीआर 657: **(1985) 4 एससीसी 417;** इंदरप्रीत सिंह काहलों बनाम पंजाब राज्य (2006) सप. 1 एससीआर 772: **(2006) 11 एस. सी. सी. 356;** संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग [2007] एस. सी. आर. 1 235: **(2007) 3 एससीसी 720;** बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद साह [2000] 2 एससीआर 299: **(2000) 4 एस. सी. सी. 640;** उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनमोहन लाल श्रीवास्तव [1958] 1 एस. सी. आर. 533: **आकाशवाणी (1957) एससी 912;** राजेन्द्र सिंह वर्मा बनाम उपराज्यपाल (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [2011] 12 एस. सी. आर. 496: **(2011) 10 एससीसी 1;** उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता-रिकॉर्ड संघ बनाम भारत संघ [1993] सप. 2 एससीआर 659: **(1993) 4 एससीसी 441;** हरि दत्त कैंथला बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [1980] 3 एससीआर

364: **(1980) 3 एस. सी. सी. 189;** गोवा न्यायिक ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम गोवा राज्य **(1997) 4 बी. ओ. एम. सी. आर. 372;** मलिक मजहर बनाम यू. पी. लोक सेवा आयोग [2006] 3 एससीआर 689: **(2006) 9 एस. सी. सी. 507-संदर्भित।**

उद्धृत पुस्तकें और पत्रिकाएँ

माइकल जे सैंडल, द टायरेनी ऑफ मेरिटःआम भलाई का क्या हुआ है?(एलन लेन, 2020) **- संदर्भित।**

वेबसाइटें

दीक्षा सान्याल और श्रीयम गुप्ता, "विवेक और विलम्बःजिला और सिविल न्यायाधीश बनने की चुनौती "(दिसंबर 2018) <https://vidhilegalpolicy.in/research/2019-1-7-discretion-and-delaychallenges-of-becoming-a-district-and-civil-judge/> 3 मई 2024 को पहुँचा गया, -**संदर्भित।**

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान; बिहार सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 1951; बिहार सुपीरियर न्यायिक (संशोधन) नियम 2013; गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2005; गुजरात न्यायिक सेवा भर्ती नियम, 1961; गुजरात राज्य न्यायिक सेवा (संशोधन) नियम, 2011; गुजरात राज्य न्यायिक सेवा (संशोधन नियम, 2014); गुजरात लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1960।

मुख्य शब्दों की सूची

न्यायिक अधिकारियों की भर्ती; न्यायिक अधिकारियों की सीधी भर्ती द्वारा जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) बार से; सिविल न्यायाधीश का पद; मौखिक परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक; बिहार और गुजरात राज्यों में जिला न्यायपालिका; अखिल भारतीय न्यायाधीश (2002)

मामला; शेट्टी आयोग की सिफारिशें; अंकों में बदलाव और सुधारात्मक कदम; लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श न करना; साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक; शेट्टी आयोग की सिफारिशों और भर्ती नियमों के बीच असंगति; अंतराल को भरने के लिए पूरक वैधानिक नियम; भर्ती प्रक्रिया; न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में एकरूपता; नियुक्ति के लिए चयन मानदंड के हिस्से के रूप में वाइवा वॉयस टेस्ट; वैध अपेक्षा; लोक सेवा आयोग; रिट याचिका, रखरखाव; रोक का सिद्धांत; मध्यस्थता; न्यायिक प्रक्रिया का सिद्धांत।

मामले से उद्दत

दिवानी मूल अधिकारिताः 2016 की रिट याचिका (सिविल) सं. 251

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

के साथ

रिट याचिका (सी) 2021 की संख्या 663 और 735, 2022 की संख्या 1073 और 1146 और 2023 की संख्या 785

पदभारों की उपस्थिति

अजीत कुमार सिन्हा, रामेश्वर सिंह मलिक, यतींद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , दीपक गोयल, मिथिलाश कुमार जयसवाल, सुश्री अलका गोयल, सुश्री उर्वशी शर्मा, सुश्री हर्षिता माहेश्वरी, कुमार कार्तिकेय, श्रीमती अर्चना प्रीति गुप्ता, नवीन सोनी, विपिन कुमार सक्सेना, जितेश मलिक, बी. सी. भट्ट, श्रीमती लीलावती सुमन, एन. डी. कौशिक, सतीश कुमार, अनिल कुमार साहू, अरविंद गुप्ता, प्रकाश गौतम, सुजीत कुमार, अरुणांश भारती गोस्वामी, ब्रह्मा प्रकाश, पवनश्री अग्रवाल, सुनील कुमार जैन, सुश्री राशिका स्वरूप, ऋषभ संचेती, सुश्री पद्म प्रिया। , गर्वित शर्मा, के. परी वेंधन, सुश्री श्रद्धा देशमुख, अर्जुन सिंह भाटी, गुरदीप सिंह, गौतम नारायण, सुश्री स्मिता सिंह, हर्षित गोयल, सुजय जैन, के. प्रसाद, पूर्विश जितेंद्र मलकान, सुश्री धरिता पूर्विश मलकान, आलोक कुमार, कुश गोयल, सुश्री दीपा गोरसिया, सुश्री

दीपानविता प्रियंका, सुश्री प्रेरणा सिंह, गुंटूर प्रभाकर, प्रमोद गुंटूर कुमार, ललित कुमार, देवेंद्र सिंह, मृत्युंजय कुमार सिन्हा, श्रीमती विमल सिन्हा, अभय कुमार, बी. एस. राजेश ए. जी। रजत, सुश्री राजबाला, सुश्री मीतू गोस्वामी, श्यामल कुमार, कृष्णवानी शर्मा, हितेश कुमार शर्मा, अखिलेश्वर झा, संदीप सिंह डिंगरा, सुश्री तनिष्का ग्रोवर, अमित कुमार चावला, वेरेंद्र मोहन, सुश्री निहारिका देवीवेदी, रंजीत कुमार शर्मा, अमित पवन, रत्नेश कुमार शुक्ला, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, विमल दुबे, मुकेश कुमार सिंह, रवि चंद्र प्रकाश, सुश्री वाणी व्यास, अनूप कुमार, मेसर्स पारेख एंड कंपनी, एड.उपस्थित दलों के लिए।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

फैसला

हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति।

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इन छह रिट याचिकाओं में आम चुनौती क्रमशः बिहार और गुजरात राज्यों में जिला न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए चयन मानदंड के एक हिस्से के रूप में मौखिक परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंकों को निर्धारित करने वाले नियमों की संवैधानिकता है। रिट याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के भाग III में निहित अनुच्छेद 14 और 16 के तहत अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इन मामलों में विशिष्ट विचार यह किया जाना चाहिए कि क्या वाइवा वॉस के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करना इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य[1] (संक्षेप में "अखिल भारतीय न्यायाधीश (2002)) जिन्होंने न्यायमूर्ति के. जे. शेट्टी आयोग की कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया (संक्षेप में "शेट्टी आयोग") का उल्लंघन है। यह भर्ती बिहार राज्य के लिए बार (2015 विज्ञापन) और गुजरात राज्य के लिए सिविल जज (2019 और

2022 विज्ञापन) के पद से सीधी भर्ती द्वारा विभिन्न रैंकों और संबंधित चयन चक्रों यानी जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के न्यायिक अधिकारियों के चयन से संबंधित है। रिट याचिकाओं में व्यक्तिगत तथ्य अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन कानूनी तर्क मोटे तौर पर ओवरलैप होते हैं। जहां भी आवश्यक होगा, व्यक्तिगत तथ्यों और कानूनी तर्कों पर अलग से विचार किया जाएगा।

I. तथ्य

2. 2016 की रिट याचिका अर्थात डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 251 (जिसे यहाँ प्रमुख मामले के रूप में माना गया है), बिहार राज्य में बार परीक्षा (2015) से सीधे जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) की भर्ती से संबंधित है। भर्ती प्रक्रिया बिहार उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1951 (संक्षेप में "बिहार नियम, 1951") द्वारा शासित होती है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है। रिट याचिका में है बिहार उच्च न्यायिक (संशोधन) के परिशिष्ट "सी" का खंड 11 नियम 2013 जो शेट्टी आयोग की सिफारिश के विपरीत होने का अनुमान है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अखिल भारतीय न्यायाधीशों (2002) में पैराग्राफ 37 और 38 में स्वीकार किया गया है को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। रिट याचिका में दूसरा अनुरोध विज्ञापन संख्या 1/2015 के तहत बिहार सुपीरियर न्यायिक सेवा के लिए चयन को अलग करना है, जैसा कि दिनांक 08.04.2016 के नोटिस के माध्यम से प्रकाशित किया गया है।

3. संबंधित मामले अर्थात डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 663/2021, डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 735/2021, डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 1073/2022, डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 1146/2022 और डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 785/2023 गुजरात में सिविल जज के पद पर भर्ती से संबंधित हैं। इसमें रिट याचिकाकर्ताओं ने गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2005 (संक्षेप में "गुजरात नियम, 2005") के संशोधित नियम 8 (3) के अधिकारों को चुनौती दी, जिसे

अधिसूचना दिनांक 1 द्वारा संशोधित किया गया था और साथ ही संबंधित भर्ती वर्षों के विज्ञापन के संबंधित खंडों को भी चुनौती दी। सहायक प्रार्थना लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के कुल अंकों के आधार पर एक नई चयन सूची तैयार करना है, चाहे निर्धारित कट-ऑफ अंक कुछ भी हों।

अ) बिहार चयन प्रक्रिया (2015)

4. मुख्य रिट याचिका 46 असफल उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई है जिन्होंने 2015 में जिला न्यायाधीश (बार से प्रत्यक्ष) परीक्षा में भाग लिया था। बिहार नियम, 1951 31.7.1951 पर लागू हुआ। बिहार नियम, 1951 में संशोधन दिनांक 1 की अधिसूचना द्वारा लाया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बिहार सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में चयन के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट, एक लिखित मुख्य परीक्षा और एक साक्षात्कार का भी प्रावधान किया गया था। मुख्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में कुल अंक क्रमशः 250 और 50 अंक थे। अर्हता प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवारों को मुख्य लिखित परीक्षा में 250 अंकों (60 प्रतिशत) में से कम से कम 150 अंक और वाइवा वॉस खंड में कुल 50 अंकों (20 प्रतिशत) में से कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होते थे।

4.1. बिहार नियम, 1951 के 3.12.2014 पर आगे के संशोधन के बाद, परिशिष्ट सी के खंड 10 में एक परंतुक जोड़ा गया था, जो उच्च न्यायालय को कुल मिलाकर योग्यता अंकों में ढील देने की शक्ति प्रदान करता है। बिहार नियम, 1951 के परिशिष्ट सी के खंड 10,11 और 12 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः-

> “10. एक उम्मीदवार केवल तभी साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त करेगा जब वह प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक और लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा।

बशर्ते कि यदि योग्य उम्मीदवारों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो उच्च न्यायालय न्यायपालिका के हित में योग्यता अंकों में कुल मिलाकर छूट दे सकता है, लेकिन यह छूट कुल मिलाकर 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

11. उम्मीदवारों को साक्षात्कार में 50 में से कम से कम 10 अंक प्राप्त करने चाहिए।

12. नियुक्ति के लिए विचार करने से पहले उम्मीदवार को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में उत्तीर्ण होना चाहिए। ”

4.2. बिहार सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में 99 रिक्तियों को भरने के लिए पटना उच्च न्यायालय द्वारा जनवरी 2015 में विज्ञापन संख्या 1/2015 जारी किया गया था। खंड 6 (घ) और (ङ) में विज्ञापन दिया गया है कि उम्मीदवारों को साक्षात्कार खंड में 50 में से कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होंगे।

4.3. जनवरी 2015 में उपरोक्त विज्ञापन के जवाब में, 22.03.2015 को आयोजित परिक्षा प्रारंभिक में लगभग 6771 उम्मीदवार उपस्थित हुए। स्क्रीनिंग टेस्ट में 176 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों को मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए मंजूरी दी गई थी। कुछ असफल उम्मीदवारों ने प्रश्न तैयार करने और संशोधित मॉडल उत्तरों में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की थीं। अंततः, उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर, स्क्रीनिंग टेस्ट में 173 या उससे अधिक के कम अंकों वाले लोगों को भी "अस्थायी रूप से" मुख्य परीक्षा लिखने की अनुमति दी गई। मुख्य लिखित परीक्षा 12.7.2015 पर आयोजित की गई थी जिसमें लगभग 1000 उम्मीदवार (प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण) उपस्थित हुए थे।

4.4. हालांकि, केवल 3 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में योग्यता अंक यानी 55 प्रतिशत से अधिक प्राप्त करने के लिए पाया गया। तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय की चयन

और नियुक्ति समिति के पांच न्यायाधीशों ने अपनी दिनांकित 8.1.2016 की बैठक में अंकों को कम करने का प्रस्ताव रखा। इससे व्यक्तिगत उम्मीदवारों के संबंधित अंकों में पेपर 1 में 4 प्रतिशत और पेपर 2 में 6 प्रतिशत अंक जुड़ गए।

4.5. उपरोक्त संयम अभ्यास के बावजूद, बहुत कम उम्मीदवार कुल मिलाकर अधिसूचित 55 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सके। इस मुद्दे को हल करने के लिए, चयन और नियुक्ति समिति ने बिहार नियम 1951 के परिशिष्ट-'सी' के खंड 10 के प्रावधान के तहत विकल्पों का उपयोग करके कुल मिलाकर 5 प्रतिशत की छूट की अनुमति दी। पूर्ण न्यायालय ने लिखित परीक्षा में कुल अंकों में 50 प्रतिशत की छूट का समर्थन किया। इसके साथ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले 81 उम्मीदवारों ने साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त की, और उनके परिणाम 22.1.2016 को घोषित किए गए।

4.6. इस बीच, पटना उच्च न्यायालय ने 8.1.2016 पर उन उम्मीदवारों की रिट याचिका (सी.डब्लू.जे.सी सं. 11731/2015) को खारिज कर दिया, जिन्हें पहले एक अंतरिम आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी, मुख्य लिखित परीक्षा में इस घोषणा के साथ उपस्थित होने के लिए कि जिन उम्मीदवारों ने स्क्रीनिंग परीक्षा में 176 से कम अंक प्राप्त किए थे, वे मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए अयोग्य हैं। तदनुसार, 176 से कम अंक प्राप्त करने वाले 5 ऐसे उम्मीदवारों को 1.2.2016 पर अयोग्य घोषित कर दिया गया। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, 3 अन्य शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को वकीलों के रूप में अभ्यास नहीं करते हुए पाया गया और इस प्रकार वे अयोग्य पाए गए। अंत में, फरवरी में आयोजित साक्षात्कार के लिए 69 उम्मीदवारों को 2016 में उच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा। वाइवा वॉयस टेस्ट के बाद, बोर्ड के व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा दिए गए अंकों के औसत की गणना करने के बाद, यह पाया गया कि केवल 9 उम्मीदवारों ने साक्षात्कार खंड में 50 में से

न्यूनतम 10 अंक प्राप्त किए थे। पटना उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने 5.4.2016 पर आयोजित अपनी बैठक में इन 9 उम्मीदवारों की नियुक्ति को मंजूरी दी और उन्हें 17.5.2016 पर नियुक्त किया गया।

4.7. बिहार में चयन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए, साक्षात्कार में न्यूनतम 10 अंक प्राप्त नहीं करने के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करने वाले 46 उम्मीदवारों ने इस अदालत का रुख किया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, बिहार नियम 1951 (3.4.2013 पर संशोधित) के परिशिष्ट-सी के खंड 11 की वैधता को इस रिट याचिका में चुनौती दी गई है। इस न्यायालय द्वारा 2.5.2016 पर रिट याचिका में नोटिस जारी किया गया था।

4.8. जब पटना उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका का जवाब देने के लिए जवाब तैयार किया जा रहा था, तो मुख्य परीक्षा में डिकोडिंग, सारणीकरण और अंकों के मिलान के दौरान कुछ विसंगतियां देखी गईं और उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने 1.6.2016 पर चयन और नियुक्ति समिति को त्रुटियों के बारे में अवगत कराया। फिर समिति के अध्यक्ष ने पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नए सिरे से सारणीकरण का आदेश दिया। अभिलेखों के विस्तृत सत्यापन के बाद, यह पाया गया कि 3 और उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में योग्यता अंक प्राप्त किए थे और इस तरह वे साक्षात्कार खंड में उपस्थित होने के योग्य थे। साथ ही यह भी पाया गया कि 4 उम्मीदवारों ने पहले अर्हता प्राप्त की थी, वास्तव में योग्यता अंक प्राप्त नहीं किए थे। परिणामी पाठ्यक्रम सुधारों के बाद, 3 और उम्मीदवारों को साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति दी गई और 4 उम्मीदवारों के लिए एक शुद्धिपत्र जारी किया गया, जिन्हें गलत तरीके से योग्य दिखाया गया था। फिर 3 उम्मीदवारों का साक्षात्कार 19.7.2016 पर आयोजित किया गया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी साक्षात्कार खंड में निर्धारित न्यूनतम 10 अंक प्राप्त नहीं किए।

दो सेवारत न्यायिक अधिकारियों ने बार सदस्यों के लिए 25 प्रतिशत कोटे के तहत आवेदन किया था और 9.8.2016 पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक न्यायिक आदेश के तहत, दोनों न्यायिक अधिकारियों को अपनी नौकरी से इस्तीफा देने की आवश्यकता के बिना चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। उनमें से एक ने साक्षात्कार खंड में उपस्थित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं किए थे और तदनुसार, केवल एक व्यक्ति (सुनील कुमार सिंह) को 31.8.2016 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। लेकिन चूंकि संबंधित उम्मीदवार साक्षात्कार में न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करने में विफल रहा, इसलिए उसे भी नहीं चुना गया।

ब) बिहार में 2015 के बाद के विकास

5. अगस्त 2016 में, पटना उच्च न्यायालय ने 98 रिक्तियों (2015 की परीक्षा के 90 रिक्त पदों सहित) के लिए जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पदों को भरने के लिए एक और विज्ञापन जारी किया। इस बीच, बिहार नियम 1951 में संशोधन करने और साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 अंकों की कट-ऑफ आवश्यकता को हटाने का प्रस्ताव किया गया था। अगस्त 2016 के विज्ञापन में साक्षात्कार खंड में न्यूनतम योग्यता अंक प्रदान नहीं किया गया था। पूर्ण न्यायालय द्वारा 22.6.2016 पर नियमों के उपयुक्त इन-ट्यून संशोधन को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद, बिहार नियम 1951 को फिर से 16.2.2017 पर संशोधित किया गया और बिहार नियम 1951 के परिशिष्ट-सी के खंड 10,11 और 12 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गयाः-

> “10. थ्योरी पेपर और वाइवा-वॉयस के अंकों का अनुपात 80 प्रतिशत और 20 प्रतिशत होगा।

11. एक उम्मीदवार को वाइवा-वॉयस के लिए तभी बुलाया जाएगा जब वह प्रत्येक थ्योरी पेपर में कम से कम 45 प्रतिशत हासिल करेगा।

12. एक उम्मीदवार नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त करेगा यदि उम्मीदवार प्रत्येक थ्योरी पेपर में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और लिखित परीक्षा (थ्योरी पेपर) और वाइवा-वॉयस में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। ”

5.1. उपरोक्त संशोधन के बाद, 2016 की भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई और विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध मार्च 2018 में 98 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई।

5.2. वर्ष 2019 में विज्ञापन के माध्यम से पूर्व उल्लिखित संशोधित नियमों के तहत 16 रिक्तियों के लिए आगे की परीक्षाएँ आयोजित की गईं, जिनमें से 12 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था। 2020 में आयोजित अगली परीक्षा में 16 और उम्मीदवारों का चयन किया गया और उन्हें नियुक्त किया गया।

5.3. उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के बाद क्रमशः वर्ष 2016,2019 और 2020 में बिहार नियम 1951 में संशोधन किया गया जिसके द्वारा परिशिष्ट-सी के खंड 12 को प्रतिस्थापित किया गया। संशोधित खंड 12 निम्नानुसार हैः

“12. एक उम्मीदवार नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त करेगा यदि उम्मीदवार प्रत्येक थ्योरी पेपर में कम से कम 45 प्रतिशत अंक, वाइवा-वॉयस/साक्षात्कार में 30 प्रतिशत अंक और लिखित परीक्षा (थ्योरी पेपर) और वाइवा-वॉयस में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। ”

5.4. 6.1.2020 पर किए गए उपरोक्त संशोधन के साथ, बिहार सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में चयन के इच्छुक उम्मीदवार को भर्ती के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए

साक्षात्कार में 30 प्रतिशत अंक और लिखित परीक्षा और वाइवा-वॉयस टेस्ट में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

(स) गुजरात चयन प्रक्रिया

6. गुजरात में चयन प्रक्रिया से संबंधित पांच रिट याचिकाओं के समूह के लिए, प्रासंगिक तथ्य डब्ल्यू. पी. (सी) 663/2021 से लिए गए हैं। जिन मुख्य तथ्यों पर चुनौती दी गई है, वे इन मामलों में काफी हद तक समान हैं। गुजरात नियम, 2005 ने प्रतिस्थापित किया पूर्ववर्ती गुजरात न्यायिक सेवा भर्ती नियम, 1961। द. गुजरात नियम, 2005 में सबसे पहले गुजरात द्वारा संशोधन किया गया। राज्य न्यायिक सेवा (संशोधन) नियम, 2011 दिनांक 23.6.2011 और दूसरा गुजरात राज्य न्यायिक सेवा (संशोधन) द्वारा नियम, 2014) दिनांक 9.9.2014। संशोधनों के अनुसार, नियम 8 में जिला न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश के संबंधित संवर्गों में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए थेः

> "8. प्रतियोगी परीक्षाः-
>
> (1) जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीशों के संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित शामिल होंगेः-
>
> (i) अधिकतम 200 अंकों के साथ कम से कम दो घंटे की अवधि की लिखित परीक्षा; और (ii) अधिकतम 50 अंकों की मौखिक परीक्षा।
>
> (2) जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में पचास प्रतिशत (50 प्रतिशत) या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार वाइवा-वॉस के लिए बुलाए जाने के पात्र होंगे।

बशर्ते कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जो सिविल न्यायाधीशों के संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में पैंतालीस प्रतिशत (45 प्रतिशत) या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, वे वाइवा-वॉस के लिए बुलाए जाने के पात्र होंगे।

(3) जिला न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए आयोजित वाइवा-वॉयस में न्यूनतम योग्यता अंक चालीस प्रतिशत (40 प्रतिशत) अंक होंगे।

(4) मेधा सूची लिखित परीक्षा और वाइवा-वॉस टेस्ट (साक्षात्कार) में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

(5) वाइवा-वॉस टेस्ट (साक्षात्कार) का उद्देश्य कैडर के लिए उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, कानून का ज्ञान, स्पष्ट और तार्किक व्याख्या, निर्णय संतुलन, कौशल, दृष्टिकोण, नैतिकता, आत्मसात करने की शक्ति, संचार की शक्ति, चरित्र और बौद्धिक गहराई और इसी तरह का आकलन करके कैडर के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करना है।

(6) भर्ती के इन नियमों में सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का प्रावधान नहीं होने पर, निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ”

6.1. उपरोक्त संशोधित नियमों के साथ, गुजरात में सिविल न्यायाधीशों की भर्ती के लिए 26.8.2019 पर एक विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा के लिए परीक्षा और पाठ्यक्रम की योजना को अधिसूचित किया गया था। खंड 5 (II) (बी) के तहत, यह निर्दिष्ट किया गया था कि वाइवा-वॉयस टेस्ट 50 अंकों का होगा। खंड 5 (II) (बी) के उपखंड (ii) के तहत वाइवा-वॉस परीक्षण का उद्देश्य निम्नानुसार इंगित किया गया थाः

"(II) (B) (i) * * * * * *

(ii) वाइवा-वॉस टेस्ट का उद्देश्य मानसिक सतर्कता, कानून का ज्ञान, स्पष्ट और तार्किक व्याख्या, निर्णय संतुलन, कौशल, दृष्टिकोण, नैतिकता, आत्मसात करने की शक्ति, शक्ति का आकलन करके कैडर के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता उम्मीदवार के संचार, चरित्र और बौद्धिक गहराई और इसी तरह की योग्यता का आकलन करना है।

6.2. विज्ञापन में खंड 5 (II) (बी) के उपखंड (iii) के तहत यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि चयन सूची में शामिल होने के योग्य होने के लिए उम्मीदवार को मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

6.3. 8.9.2019 पर, कृतिका बोधा (डब्लू पी (सी) 663/2021), उम्मीदवारों में से एक ने सिविल जज के पद पर चयन के लिए अपना आवेदन जमा किया। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम 18.12.2019 पर घोषित किए गए थे। मुख्य लिखित परीक्षा 19.1.2020 पर आयोजित की गई थी और उसके परिणाम 24.7.2020 पर प्रकाशित किए गए थे, जिसमें 132 उम्मीदवारों को साक्षात्कार दौर के लिए सफल घोषित किया गया था। साक्षात्कार 7.3.2021 पर आयोजित किया गया था। सामान्य श्रेणी में अंतिम उम्मीदवार के 124 अंक थे और रिट याचिकाकर्ता (40 प्रतिशत से कम वाइवा वॉस अंकों के कारण), 135.33 अंक प्राप्त करने के बावजूद, चयन नहीं किया गया था। सभी पाँच रिट याचिकाओं में गुजरात नियम, 2005 (2011 में संशोधित) के नियम 8 (4) को रद्द करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें वाइवा वॉस के लिए 40 प्रतिशत योग्यता अंक निर्दिष्ट किए गए हैं। संबंधित प्रार्थनाएँ चयन सूची को रद्द करने और नए साक्षात्कार आयोजित करने के लिए हैं।

II. प्रस्तुतियाँ

7. हमने रिट याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अजीत कुमार सिन्हा, श्री जतिंदर सिंह, श्री रामेश्वर सिंह मलिक और विद्वान वकील सुश्री श्रद्धा देशमुख, श्री पवनश्री अग्रवाल और श्री ऋषभ संचेती को सुना है। विद्वान वकील श्री गौतम नारायण और श्री पूर्विश जितेंद्र मलकान ने क्रमशः पटना और गुजरात के उच्च न्यायालयों का प्रतिनिधित्व किया।

8. इन मामलों में मूलभूत चुनौती वाइवा वॉस खंड में न्यूनतम कट-ऑफ का निर्धारण है, यानी पटना उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती के लिए 20 प्रतिशत और गुजरात उच्च न्यायालय के तहत भर्ती के लिए 40 प्रतिशत।

9. रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील का तर्क है कि चयन प्रक्रिया दूषित है क्योंकि यह अखिल भारतीय न्यायाधीशों (2002) में निर्धारित कानून का उल्लंघन है जहां तीन न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों की सीधी भर्ती के मामले में शेट्टी आयोग द्वारा प्रस्तुत दिनांक 11.11.1999 की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के बाद पीठ ने राय दी कि विभिन्न संशोधनों के अधीन आयोग के निर्णय और अन्य सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। चूंकि शेट्टी आयोग ने न्यायिक अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया का सुझाव देते हुए विशेष रूप से संकेत दिया था कि साक्षात्कार खंड में बिना किसी न्यूनतम कट-ऑफ अंकों के 50 अंक होंगे, इसलिए वाइवा-वॉस टेस्ट में न्यूनतम अंकों का निर्धारण मनमाना और अनुचित है।

10. विद्वान वकील के अनुसार, रिट याचिकाकर्ताओं के पास बेहतर कुल अंक (लिखित और मौखिक-मौखिक संयुक्त) हैं, लेकिन वे केवल इसलिए चयन से वंचित हैं क्योंकि वे साक्षात्कार में योग्यता अंक प्राप्त करने में विफल रहे हैं। यह भी तर्क दिया जाता है कि साक्षात्कार के अंक मनमाने ढंग से दिए जाते हैं और यही कारण है कि शेट्टी आयोग ने वाइवा-वॉस खंड में अंकों की कट-ऑफ को समाप्त करने की सिफारिश की।

11. मुख्य रिट याचिका में उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री अजीत कुमार सिन्हा बिहार चयन प्रक्रिया में विसंगतियों पर प्रकाश डालते हैं। पटना उच्च न्यायालय के तहत चयन प्रक्रिया की घुमावदार प्रकृति और अंकों के मॉडरेशन और लिखित परीक्षा में कुल अंकों में 5 प्रतिशत की और छूट देने के लिए लिए गए निर्णय पर टिप्पणी करते हुए, श्री सिन्हा ने तर्क दिया कि साक्षात्कार खंड के लिए अंकों के मॉडरेशन पर विचार किया जाना चाहिए था, साथ ही उन लोगों के चयन की सुविधा के लिए जिन्होंने लिखित परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए थे, लेकिन साक्षात्कार खंड में केवल नीचे दिए गए कट ऑफ अंक प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे। विद्वान वकील उस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है जिसमें बार-बार पाठ्यक्रम सुधार की आवश्यकता होती है जैसे कि मॉडरेशन का सहारा लेना और लिखित परीक्षा खंड में कुल अंकों में छूट, जैसा कि पटना उच्च न्यायालय के अतिरिक्त हलफनामे में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि न्यायालय को न केवल दोषपूर्ण चयन प्रक्रिया पर उचित आदेश पारित करना चाहिए, बल्कि वाइवा खंड में कट-ऑफ अंक बार को लागू किए बिना कुल अंक (लिखित + वाइवा) के आधार पर नियुक्ति की अनुमति भी देनी चाहिए।

12. याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, आईडी1 पर अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद भी, चयन और नियुक्ति समिति ने सितंबर, 2016 तक शुद्धिपत्र जारी करके, लिखित परीक्षा का नया परिणाम प्रकाशित करके, कुछ उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित करके और अंतिम परिणाम प्रकाशित करके कार्य करना जारी रखा। इसके बाद श्री सिन्हा ने तर्क दिया कि अगर पटना उच्च न्यायालय एक बड़े समूह से उम्मीदवारों पर विचार करना चाहता है, तो रिक्तियों की बड़ी संख्या के कारण साक्षात्कार खंड में योग्यता अंकों में छूट एक स्वाभाविक विकल्प होना चाहिए था।

13. विद्वान वकील श्री पवनश्री अग्रवाल ने अपनी ओर से प्रस्तुत किया कि गुजरात चयन बोर्ड में साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों के पास उम्मीदवारों के लिखित अंकों तक पहुंच थी और इसलिए साक्षात्कार बोर्ड के लिए किसी मेधावी उम्मीदवार को योग्यता से कम अंक देकर मनमाने ढंग से अयोग्य घोषित करना संभव था। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि नियमों में संशोधन 2011 में केवल गुजरात उच्च न्यायालय के परामर्श से किया गया था, लेकिन गुजरात लोक सेवा आयोग के परामर्श से नहीं। इसलिए इस तरह का संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 का उल्लंघन करता है।

14. इसी तर्ज पर, डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 1146/2022 में उपस्थित विद्वान वकील श्री ऋषभ संचेती ने तर्क दिया कि वाइवा-वॉस खंड में समान अंक से कम होने के कारण नियुक्ति से इनकार करना भेदभावपूर्ण है क्योंकि इस तरह की शक्ति का उपयोग योग्य उम्मीदवारों को बाहर करने के लिए किया जा सकता है।

15. इसके विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए, पटना उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील, श्री गौतम नारायण ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय को सर्वश्रेष्ठ चयन करने के लिए शेट्टी आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों की तुलना में सख्त मानदंड लागू करने का विवेकाधिकार है। श्री नारायण के अनुसार, शेट्टी आयोग द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया केवल अनुशंसित है। विद्वान वकील के अनुसार शेट्टी आयोग की सिफारिशों को केवल दिशानिर्देशों के रूप में माना जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पटना उच्च न्यायालय ने व्यापक रूप से जिला न्यायपालिका के लिए भर्ती प्रक्रिया का पालन किया और इसे केवल थोड़ा और कठोर बना दिया। इसका उद्देश्य मेधावी न्यायिक अधिकारियों का चयन सुनिश्चित करना और अंततः जिला न्यायपालिका के मानक को बनाए रखना था। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि असफल उम्मीदवारों के कहने पर रिट याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं।

16. श्री नारायण की अन्य दलीलों को स्वीकार करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान वकील श्री पूर्विश मलकन का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 233,234 और 235 के तहत अपनी प्रक्रिया विकसित करने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास निहित है। इसके साथ श्री मलकान उच्च न्यायालय द्वारा नियमों में संशोधन का समर्थन करते हैं। विद्वान वकील उच्च न्यायालय के जवाबी हलफनामे को यह तर्क देने के लिए संदर्भित करता है कि आंतरिक बोर्ड के सदस्यों को मौखिक परीक्षा आयोजित करते समय लिखित परीक्षा में अंकों तक पहुंच नहीं थी।

III. मुद्दे

17. जिन मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए वे

i) क्या वाइवा वॉस के लिए न्यूनतम अंकों का निर्धारण अखिल भारतीय न्यायाधीशों (2002) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन है, जिसने शेट्टी आयोग की कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया था?

(ii) क्या वाइवा वॉस के लिए न्यूनतम अंकों का निर्धारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है?

(iii) बिहार चयन प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं द्वारा बताए गए अंकों के मोडरेशन और सुधारात्मक कदमों को देखते हुए क्या बिहार में चयन प्रक्रिया दूषित है?

(iv) क्या गुजरात राज्य में सिविल न्यायाधीश के पद पर चयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 234 के तहत लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श न करने से गुजरात नियम, 2005 (2011 में संशोधित) अमान्य हो जाएगा?

IV. पोषणीयता

18. शुरू में, रिट याचिकाओं की पोषणीयता के मुद्दे को संबोधित करना उचित है। श्री गौतम नारायण और श्री पूर्विश जितेंद्र मलकान विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के बाद, रिट याचिकाकर्ता सफल नहीं हो सकते हैं, और भर्ती प्रक्रिया या भर्ती नियमों के अधिकारों को चुनौती नहीं दे सकते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सभी उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया शुरू होने से बहुत पहले वाइवा वॉस के लिए न्यूनतम अंकों के निर्धारण के बारे में पता था और विरोध का सिद्धांत असफल चुनौती देने वालों के खिलाफ काम करेगा। दूसरी ओर, रिट याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जब चयन प्रक्रिया में स्पष्ट अवैधताएं[2] हैं तो रोक का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसके अलावा, रोक तब लागू नहीं होती है जब मनमानेपन से भारत के संविधान[3] के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं।

19. जैसा कि उच्च न्यायालयों के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है, कानूनी स्थिति यह है कि भर्ती प्रक्रिया[4] में भाग लेने के बाद, असफल उम्मीदवार मुड़कर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकते हैं। हालाँकि, यह भी तय किया गया है कि अवरोध का सिद्धांत कानून[5] को ओवरराइड नहीं कर सकता है। इस तरह के कानूनी सिद्धांत को दोहराया गया डॉ. (मेजर) मीता सहाय बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा[6] जहाँ इसे निम्नानुसार देखा गयाः

> "17. हालाँकि, हमें इस सिद्धांत से अलग होना चाहिए क्योंकि उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सहमत होकर केवल निर्धारित प्रक्रिया को स्वीकार करता है न कि इसमें अवैधता को। ऐसी स्थिति में जहां एक उम्मीदवार वैधानिक नियमों के गलत निर्माण और उससे उत्पन्न होने वाले भेदभावपूर्ण परिणामों का आरोप लगाता है, उसे केवल इसलिए माफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक उम्मीदवार ने इसमें भाग लिया है। संवैधानिक

योजना पवित्र है और किसी भी तरह से इसका उल्लंघन अस्वीकार्य है। वास्तव में, एक उम्मीदवार को संविधान के प्रावधानों की लाइलाज अवैधता या अपमान पर हमला करने का अधिकार नहीं हो सकता है, जब तक कि वह चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। ”

20. उपरोक्त अनुपात द्वारा निर्देशित, इस तरह के मामलों में, सीमा पर रिट याचिकाकर्ताओं पर मुकदमा न करना शायद ही उचित होगा, विशेष रूप से जब प्रक्रिया में कथित कमियों का अनुमान केवल चयन प्रक्रिया में भागीदारी से लगाया जा सकता है।

21. अगला सवाल यह है कि क्या इन मामलों में रेस जुडिकाटा का सिद्धांत आकर्षित होता है। गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान वकील श्री पुरविश मलकान ने हमारे ध्यान में लाया कि गुजरात नियम, 2005 (23.6.2011 पर संशोधित) के नियम 8 (3) की वैधता को पहले 2013 के डब्लू पी (सी) 291 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने दलीलें पूरी करने के बाद उक्त रिट याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद, गुजरात उच्च न्यायालय ने 2015 के विशेष सिविल आवेदन में एक विस्तृत फैसले में साक्षात्कार के लिए 40 प्रतिशत कट-ऑफ अंक निर्धारित करने वाले संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। उक्त निर्णय से उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय द्वारा 30.1.2017 पर खारिज कर दिया गया था।

22. उपरोक्त संदर्भ में, दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[7] (संक्षेप में "दरयाव") मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायिक निर्णय का सिद्धांत सार्वभौमिक अनुप्रयोग में से एक है और चूंकि अंतिम निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी है, इसलिए अनुच्छेद 226 के तहत एक आवेदक अपील

में प्रतिकूल निर्णय को दरकिनार किए बिना अनुच्छेद 32 के तहत उन्हीं आधारों पर आवेदन नहीं कर सकता है। हालाँकि, उन मामलों के बीच अंतर किया गया था जहाँ अनुच्छेद 226 के तहत आवेदन को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया है और उन मामलों के बीच जहां इसे प्रारंभिक आधार पर खारिज कर दिया गया है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि एक अनुच्छेद 32 याचिका समान तथ्यों और समान आधारों पर बनाए रखने योग्य नहीं होगी।

23. हालाँकि उपरोक्त अनुपात को वर्तमान तथ्यों में सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि यह वही रिट याचिकाकर्ता नहीं है जिसने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। यहाँ न्यायालय का सामना तथ्यों के एक अलग समूह से होता है, वादियों का एक और समूह जिन्होंने अतिरिक्त तर्क उठाए हैं। इसलिए, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री पवनश्री अग्रवाल का यह निवेदन कि रिट याचिका को न्यायिक आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए, अधिक उचित पाया गया है। किसी भी मामले में, विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने का कानून[8] के सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

24. आइए अब हम इस मौलिक प्रश्न पर ध्यान दें कि क्या साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करना अखिल भारतीय न्यायाधीशों (2002) में अनुपात का उल्लंघन करता है। ऐसा करने के लिए, निम्नलिखित प्रासंगिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना आवश्यक है।

V. शेट्टी आयोग की उत्पत्ति

25. 1989 में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और इसके कार्यकारी अध्यक्ष सेवा स्थितियों में एकरूपता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिला न्यायपालिका के सदस्यों के लिए विभिन्न राहतों की मांग करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक

रिट याचिका दायर की गई। 13.11.1991 को, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सी. जे. रंगनाथ मिश्रा के माध्यम से बोलते हुए उक्त का निपटारा किया। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ[9] में रिट याचिका, इसके बाद जिला न्यायपालिका के वेतनमान और सेवा शर्तों से संबंधित मुद्दों पर विचार करना। सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वेतन संरचना की अलग से जांच और समीक्षा करेंगे। उपरोक्त निर्णय से व्यथित भारत संघ और कुछ राज्य सरकारों ने इसके समक्ष समीक्षा याचिकाएं दायर कीं। अदालत। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ[10] (संक्षेप में "अखिल भारतीय न्यायाधीश (1993)), इस न्यायालय ने 28.8.1993 को मूल निर्णय में कुछ राहतों को संशोधित किया, लेकिन अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की कि न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों की समय-समय पर विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए गठित एक स्वतंत्र आयोग द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। 1993 के बाद से, इस न्यायालय ने 'निरंतर आदेश' के अपने रिट उपचार का प्रयोग करते हुए इस मामले के नियम के तहत कई निर्देश जारी किए थे।

26. उपरोक्त निर्देश के अनुसार, भारत संघ ने न्यायमूर्ति के. जे. शेट्टी की अध्यक्षता में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की नियुक्ति की। न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग ने 31.1.1998 पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट और 11.11.1999 पर एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग के संदर्भ की शर्तें नीचे दी गई हैं:

"(क) देश भर में अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित न्यायिक अधिकारियों के वेतन और अन्य परिलब्धियों की संरचना को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को विकसित करना।

(ख) राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायिक अधिकारियों के लिए उपलब्ध लाभों के कुल समूह को ध्यान में रखते हुए उनके परिलब्धियों और सेवा की शर्तों की

वर्तमान संरचना की जांच करना और अन्य प्रासंगिक कारकों के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायिक सेवा से संबंधित अधिकारियों और अन्य सिविल सेवकों के बीच वेतन संरचना में मौजूदा संबंध को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सिफारिशें करना।

(ग) न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यूनतम योग्यता, भर्ती की आयु, भर्ती की विधि आदि के संबंध में जांच और सिफारिश करना। इस संदर्भ में, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले और अन्य मामलों में संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखा जा सकता है।

(घ) कार्य विधियों और कार्य वातावरण के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के भत्तों और लाभों की जांच करना जो न्यायिक अधिकारियों को वेतन के अलावा उपलब्ध हैं और न्यायिक प्रशासन में दक्षता को बढ़ावा देने, न्यायपालिका के आकार को अनुकूलित करने की दृष्टि से उन्हें तर्कसंगत बनाने और सरल बनाने का सुझाव देना आदि। ”

27. उपरोक्त से संकेत मिलता है कि संदर्भ की शर्तें अनिवार्य रूप से उन सिद्धांतों के विकास पर केंद्रित हैं जो न्यायिक अधिकारियों के वेतन संरचना और परिलब्धियों के निर्माण को नियंत्रित करेंगे। न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यूनतम योग्यता, आयु और "भर्ती की विधि" आदि पर भी सुझाव अपेक्षित थे। 11.11.1999 पर प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में सेवानिवृत्ति की आयु, न्यायिक अधिकारियों के लिए नामकरण, पदों के समीकरण, अंतर-वरिष्ठता, प्रत्यक्ष भर्ती के लिए आयु, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

28. शेट्टी आयोग की रिपोर्ट के प्रासंगिक हिस्से को निकालने से पहले, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया था कि साक्षात्कार खंड के लिए कोई कट-ऑफ अंक तय नहीं किए जाने चाहिए, संदर्भ का एक संदर्भ उपयुक्त हैः"

> "10.95 हम पहले प्रत्यक्ष उम्मीदवारों के चयन के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित कर चुके हैं। भर्ती। अधिकांश उच्च न्यायालयों में केवल वाइवा वॉयस टेस्ट हो रहा है।
>
> 10.96 हालांकि, आंध्र प्रदेश, इलाहाबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के उच्च न्यायालयों ने मौखिक परीक्षा के अलावा लिखित परीक्षा भी निर्धारित की है।
>
> 10.97 आयोग को असंख्य शिकायतें मिली हैं कि केवल वाइवा-वॉस द्वारा चयन ने अक्सर मनमानेपन को जन्म दिया है, यदि सनकी चयन नहीं है, तो अन्यायपूर्ण है, यदि अनुचित नहीं है। उच्च न्यायालयों के संबंध में, हम ऐसी कोई धारणा नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन हम महसूस करते हैं कि चयन प्रक्रिया में कम पारदर्शिता और निष्पक्षता है। "

29. चूंकि अधिकांश उच्च न्यायालय लिखित परीक्षा आयोजित किए बिना केवल मौखिक परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों का चयन कर रहे थे, इसलिए साक्षात्कार प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का अभाव देखा गया। इसलिए आयोग ने राय दी कि वाइवा वॉस को एकमात्र चयन मोड के रूप में स्वीकार करने से मनमानेपन आ सकता है। हालाँकि लिखित परीक्षा के साथ वाइवा वॉयस के लिए न्यूनतम कट-ऑफ अंक निर्धारित करने से चयन में मनमानेपन कैसे आ सकता है, इस बारे में अपने आप में कोई स्पष्टता नहीं है। व्यक्तिपरकता को कम करने के लिए, शेट्टी आयोग ने अपनी

बाद की सिफारिशों में वाइवा वॉस के संचालन के लिए कार्यप्रणाली को निम्नानुसार चित्रित कियाः

"10.97.....इसलिए, हम व्यक्तिपरकता और मनमानेपन की डिग्री को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया की सिफारिश करना चाहेंगेः

(i) लिखित परीक्षा होगी जिसके बाद मौखिक परीक्षा होगी।

(ii) लिखित परीक्षा में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विषय/विषयों पर 200 अंक होने चाहिए। पेपर की अवधि कम से कम दो घंटे की होनी चाहिए।

(iii) लिखित परीक्षा में कट ऑफ अंक सामान्य उम्मीदवारों के लिए 60 प्रतिशत या संबंधित ग्रेड और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत या संबंधित ग्रेड होना चाहिए। जिन लोगों ने कट ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें वाइवा-वॉस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

(iv) वाइवा-वॉस टेस्ट पूरी तरह से और वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए और इसे प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 25 से 30 मिनट के बीच लिया जाना चाहिए। वाइवा-वॉयस में 50 अंक होंगे। वाइवा-वॉयस टेस्ट में कट-ऑफ मार्क्स नहीं होगी।

(v) योग्यता सूची लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा दोनों में प्राप्त अंकों/ग्रेड के आधार पर तैयार की जाएगी। "

30. इस बिंदु पर, रिट याचिकाकर्ताओं के तर्क में मौलिक भ्रांति, जैसा कि पटना उच्च न्यायालय के विद्वान वकील श्री गौतम नारायण द्वारा इंगित किया गया है, स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है। यदि शेट्टी आयोग द्वारा अनुशंसित उपरोक्त प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जाना है, तो लिखित परीक्षा के लिए भी कट-ऑफ अंक कभी भी 60 प्रतिशत से कम नहीं हो सकते हैं। इसलिए, यदि पटना उच्च न्यायालय की भर्ती

प्रक्रिया का परीक्षण शेट्टी आयोग के अनुशंसित सीमा अंकों यानी लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए 250 अंकों में से 150 अंकों पर किया जाता है, तो कोई भी रिट याचिकाकर्ता वाइवा-वॉयस के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने लिखित अंकों में कुल मिलाकर न्यूनतम 60 प्रतिशत कभी हासिल नहीं किया। वर्तमान मामले में, संशोधित नियमों के अनुसार न्यूनतम कट-ऑफ 55 प्रतिशत थी और इसे बिहार नियम, 1951 के खंड 10 के प्रावधान के अनुसार घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था। इसलिए रिट याचिकाकर्ताओं को वाइवा वॉस खंड में कट-ऑफ अंकों को समाप्त करने के लिए शेट्टी आयोग की सिफारिशों के चयनात्मक कार्यान्वयन के लिए बहस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, उम्मीदवारों को एक ही सांस में "अनुमोदन और खंडन"[11] करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार, शेट्टी आयोग द्वारा अनुशंसित मानदंडों को केवल वाइवा वॉस सेगमेंट के लिए कमजोर करने की मांग करना अस्वीकार्य होगा।

31. शेट्टी आयोग ने सिफारिश की कि व्यक्तिपरकता और मनमानेपन की मात्रा को कम किया जाना चाहिए और चयन पारदर्शी होना चाहिए। रिपोर्ट के पैरा 10.99 के खंड (vi) और (vii) में, इसे विशेष रूप से निम्नानुसार नोट किया गया थाः

> “(vi) आज, मौखिक परीक्षा लिखित परीक्षा की तुलना में अधिक अनुचित हो सकती है क्योंकि यह कम से कम संभव समय में संयोग या प्रभाव पर तय की जाती है। ग्रामीण उम्मीदवार आमतौर पर इस प्रक्रिया में नुकसान में होते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले उम्मीदवार कभी-कभी नौकरी के लिए कौशल में बेहतर हुए बिना लाभ प्राप्त करते हैं। साक्षात्कार बोर्ड का एक प्रमुख सदस्य कई योग्य उम्मीदवारों के लिए दिन को नुकसानदेह बना सकता है। ये चीजें जरूरी नहीं कि बोर्ड के सदस्यों के किसी भी सचेत पूर्वाग्रह या स्वभाव के कारण होती हैं। यह प्रक्रिया में ही निहित है क्योंकि यह वर्तमान में कई स्थानों पर काम करता है। न्यायपालिका चयन प्रणाली में दुर्बलताओं

के कारण सबसे उत्कृष्ट उम्मीदवार प्राप्त करने के अवसरों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती है। इस प्रकार, वाइवा वॉस के लिए भी लिखित परीक्षा की तर्ज पर एक वैकल्पिक प्रक्रिया की सिफारिश की जाती है।

(vii) वाइवा-वॉयस परीक्षा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगीः

(क) ज्ञान/कौशल/दृष्टिकोण/नैतिकता/संचार/चरित्र, जैसी श्रेणियों वाला एक प्रारूप विकसित किया जाएगा (यह इस बात पर निर्भर करेगा कि न्यायपालिका संभावित न्यायाधीशों के साक्षात्कार में किन गुणों की तलाश कर रही है) और प्रत्येक श्रेणी को अंकों के संदर्भ में सापेक्ष महत्व (श्रेय) दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कुल वाइवा अंक 100 हैं, तो कोई व्यक्ति ज्ञान/समझ के लिए 10 अंक, नैतिकता/दृष्टिकोण के लिए 5 अंक, निर्णय लेने के कौशल के लिए 25 अंक, संचार क्षमताओं के लिए 10 अंक, सामान्य ज्ञान के लिए 10 अंक आदि निर्धारित कर सकता है।

(ख) अध्यक्ष सहित बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को उम्मीदवार के साक्षात्कार के तुरंत बाद और अगले उम्मीदवार को बुलाने से पहले प्रत्येक श्रेणी के लिए अंक निर्धारित करने के लिए कहा जाएगा। सदस्यों के दृष्टिकोण में कुछ समानता या सापेक्ष समानता लाने के लिए, बोर्ड साक्षात्कार शुरू होने से पहले मूल्यांकन के एक विशेष स्तर के लिए दिए जाने वाले अंकों की सीमा पर कुछ सामान्य चर्चा कर सकता है। यदि आवश्यक हो, तो साक्षात्कार के समय अंक निर्धारित करने में पालन करने के लिए कुछ लिखित दिशानिर्देश भी प्रसारित किए जा सकते हैं।

(ग) प्रत्येक दिन के साक्षात्कार के अंत में, सारणीकार प्रत्येक श्रेणी को सौंपे गए संख्यात्मक अंकों को ग्रेड में और फिर ग्रेड मूल्यों में बदल देगा। इसके बाद इसका

योग किया जाएगा और साक्षात्कार किए गए प्रत्येक उम्मीदवार का संचयी ग्रेड मूल्य औसत प्राप्त किया जाएगा। ”

32. जैसा कि ठीक ही ऊपर उल्लेख किया गया है, अंग्रेजी बोलने वाले शहरी उम्मीदवार संभवतः ग्रामीण पृष्ठभूमि और हाशिए के समुदायों से संबंधित लोगों की तुलना में लाभ में हो सकते हैं। हालाँकि यह देखा जाना चाहिए कि शेट्टी आयोग की रिपोर्ट उच्च न्यायालयों द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित किए बिना केवल मौखिक परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने की पृष्ठभूमि में थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि शेट्टी आयोग ने न्यायिक अधिकारियों के चयन के लिए, चाहे वह लिखित परीक्षा में हो या मौखिक परीक्षा में, संख्यात्मक अंकों के बजाय ग्रेड के माध्यम से मूल्यांकन की सिफारिश की थी। इसने यह भी सुझाव दिया कि साक्षात्कार के समय अंक निर्धारित करने के लिए लिखित दिशानिर्देश होने चाहिए।

VI. इस पर विवेकपूर्ण चर्चा

मुद्दा संख्या 1) क्या वाइवा वॉस के लिए न्यूनतम अंकों का निर्धारण इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून- अखिल भारतीय न्यायाधीश (2002), जिन्होंने शेट्टी आयोग की कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया था का उल्लंघन है।

33. अखिल भारतीय न्यायाधीशों (2002) के फैसले का अब उपरोक्त प्रारंभिक संदर्भ में विश्लेषण करना होगा। न्यायालय ने कुछ अन्य को संशोधित या अस्वीकार करते हुए शेट्टी आयोग द्वारा की गई कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। पैराग्राफ 27 में, 3-न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति बी. एन. कृपाल के माध्यम से बोलते हुए विशेष रूप से इस प्रकार उल्लेख कियाः

> “27. … साथ ही, हमारी राय है कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के रूप में उच्च न्यायिक सेवा में प्रवेश करने वाले अधिकारियों के

लिए निश्चित न्यूनतम मानक, वस्तुनिष्ठ रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए। हालांकि हम शेट्टी आयोग से सहमत हैं कि उच्च न्यायिक सेवा यानी जिला न्यायाधीश संवर्ग में अधिवक्ताओं में से 25 प्रतिशत भर्ती होनी चाहिए और भर्ती की प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए। परीक्षा, लिखित और मौखिक दोनों, हमारी राय हैं कि उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति के लिए अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की उपयुक्तता का परीक्षण करने का एक वस्तुनिष्ठ तरीका होना चाहिए। ”

[जोर दिया गया]

34. उपरोक्त से पता चलता है कि भर्ती की विधि से निपटने के दौरान, इस न्यायालय ने भर्ती के लिए एक वस्तुनिष्ठ मानक के महत्व पर जोर दिया और इस बात पर जोर दिया कि सीधी भर्ती की प्रक्रिया लिखित और मौखिक परीक्षा के माध्यम से होनी चाहिए। पूरे फैसले को ध्यान से पढ़ने से पता चलेगा कि पैराग्राफ 27 में टिप्पणी के अलावा वाइवा वॉस के पहलू पर कोई सीधी चर्चा नहीं है कि उपयुक्तता परीक्षण की एक वस्तुनिष्ठ विधि होनी चाहिए। वाइवा-वॉयस के लिए न्यूनतम योग्यता अंक होने चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर अदालत का ध्यान नहीं गया। इसके अलावा, शेट्टी आयोग की रिपोर्ट में भी कोई विशिष्ट तर्क नहीं दिया गया कि वाइवा वॉस के लिए न्यूनतम अंक क्यों नहीं होने चाहिए। इस चर्चा के लिए, हम हाल ही का उल्लेख करके लाभान्वित हो सकते हैं डा. कम्बोज बनाम पंजाब उच्च न्यायालय में इस न्यायालय का निर्णय और हरियाणा और अन्य[12] (संक्षेप में "कविता खंबोज")। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखा अखिल भारतीय न्यायाधीशों (2002) में पूर्व निर्णय और विशेष रूप से उल्लिखित किया कि न्यायालय ने सामान्य रूप से न्यूनतम कटौती की वांछनीयता या अन्यथा के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। फैसले का निम्नलिखित अंश यहां प्रासंगिक हैः-

> “41. अब यह सच है कि न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान में सुधार के संबंध में शेट्टी आयोग की कुछ सिफारिशों को इस न्यायालय ने अखिल भारतीय न्यायाधीशों के मामले में इस न्यायालय के फैसले में स्वीकार कर लिया था। एसोसिएशन (ऊपर)। हालाँकि, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (उपरोक्त) के पैराग्राफ 27 और 28 में इस संबंध में कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं था कि नियमित पदोन्नति के माध्यम से भर्ती के लिए कट-ऑफ लगाई जानी चाहिए या नहीं। न्यायालय ने केवल यह टिप्पणी की थी कि "अधीनस्थ न्यायपालिका की उपयुक्तता का परीक्षण करने का एक वस्तुनिष्ठ तरीका होना चाहिए", सामान्य रूप से वाइवा वॉस के लिए न्यूनतम कटऑफ की वांछनीयता या अन्यथा के बारे में कोई अवलोकन किए बिना। ”
>
> [जोर दिया गया]

35. उपरोक्त निर्णय में पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय को राज्य में सेवा की आवश्यकताओं के आधार पर न्यूनतम कटौती निर्धारित करने वाले नियम बनाने से रोका नहीं जा सकता है।

36. वर्तमान मामले में, रिट याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त तर्क दिया कि अखिल भारतीय न्यायाधीशों (2002) में अनुच्छेद 37 के आधार पर, न्यायालय ने स्वीकार किया यहाँ तक कि वे सिफारिशें जिन पर निर्णय में अन्यथा चर्चा नहीं की गई थी। उक्त अनुच्छेद इस प्रकार हैः

> “37. इस निर्णय में विभिन्न संशोधनों के अधीन, शेट्टी आयोग की अन्य सभी सिफारिशें स्वीकार की जाती हैं। ”

37. उपरोक्त अनुच्छेद हमें यह निष्कर्ष निकालने के लिए राजी नहीं कर सकता है कि इस न्यायालय ने साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों को समाप्त करने की शेट्टी आयोग की

सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि न्यायालय ने पिछले पैराग्राफ में शेट्टी आयोग की विभिन्न सिफारिशों को सूचीबद्ध किया था। साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों के साथ वितरण हालांकि उक्त सूची में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इस तरह के विशिष्ट उल्लेख के बिना, यह कहना तर्कसंगत होगा कि अखिल भारतीय न्यायाधीशों (2002) में निर्णय साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों के पहलू पर मौन है। इसलिए इस फैसले को साक्षात्कार खंड में न्यूनतम कट-ऑफ अंकों को समाप्त करने पर आधिकारिक रूप से स्पष्ट होने के रूप में नहीं माना जा सकता है।

38. आइए अब हम उन अन्य मामलों की ओर मुड़ें जहां इस न्यायालय को ऐसी स्थितियों में शेट्टी आयोग की सिफारिशों की व्याख्या करने का अवसर मिला था जहां भर्ती नियम सिफारिशों के साथ असंगत थेः

i) सैयद टी. ए. नक्शबंदी बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य[13] में, प्रधानता देते हुए उच्च न्यायालय द्वारा नीतिगत निर्णयों और पूर्ण न्यायालय के प्रस्तावों के संबंध में बनाए गए नियमों के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां कींः

> “8. रिलायंस ने न्यायमूर्ति जगन्नाथ शेट्टी आयोग की सिफारिशों या अखिल भारतीय न्यायाधीशों की एसोसिएशन बनाम भारत संघ [(2002) 4 एस. सी. सी. 247 में रिपोर्ट किए गए निर्णय पर रखाः2002 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 508] या यहाँ तक कि उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय का दिनांकित 27-4-2002 का संकल्प न केवल अनुचित है, बल्कि गलत है और इस धारणा के आधार पर समर्थन की गई शिकायतें केवल उल्लेख के योग्य हैं जिन्हें अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। उस मामले के लिए किसी भी सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तें वैधानिक नियमों और आदेशों द्वारा शासित होती हैं,

जो उस क्षेत्र को कवर करने के लिए नियमों के अभाव में कानूनी रूप से बनाए गए हैं जो विशेष रूप से ऐसे नियमों द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, और जब तक कि उन्हें कानून द्वारा ज्ञात तरीके से प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जाता है, तब तक किसी के लिए भी उन मौजूदा नियमों/आदेशों को नजरअंदाज करने का दावा करना व्यर्थ होगा जो उन्हें बदलने, संशोधित करने या संशोधित करने के लिए भी लिए गए कुछ नीतिगत निर्णयों के लिए जगह देते हैं। ”

(ii) राखी रे बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय[14] में, उच्चतम न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि आयोग की सिफारिशों को भले ही इस न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों में शामिल करने की आवश्यकता है। हालांकि, किसी विशेष मुद्दे से निपटने के लिए वैधानिक नियम के अभाव में, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को प्रभावी बनाने के लिए बाध्य हैं।

iii) इसी तरह महिंदर कुमार बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय[15] (संक्षेप में "महिंदर कुमार") के लिए, चुनौती जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) की भर्ती के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के लिए थी। शेट्टी आयोग के अनुच्छेद 10.97 पर चर्चा करते हुए, 3 न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति एफ. एम. इब्राहिम कलीफुल्ला के माध्यम से बोलते हुए स्पष्ट कियाः

“71. शेट्टी आयोग रिपोर्ट के पैरा <आई. डी. 1 के उप-पैरा (i) से (v) को यह दिखाने के लिए निर्धारित किया गया है कि लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा आयोजित करते समय, अंकों के निर्धारण और अन्य पहलुओं का पालन कैसे किया जाना चाहिए। वास्तव में शेट्टी आयोग की रिपोर्ट के पैरा 10.97

में निहित उन उप-अनुच्छेदों को एक दिशानिर्देश कहा जा सकता है, जिसे किसी भी उच्च न्यायालय को उच्च न्यायिक सेवा में पदों को भरने के लिए चयन का सहारा लेते समय ध्यान में रखना चाहिए। इस संदर्भ में, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के पैरा 28 में। (3) [(2002) 4 एससीसी 247:2002 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 508], इस न्यायालय ने जिला न्यायाधीशों के लिए उच्च न्यायिक सेवा के पद के लिए उच्च न्यायिक सेवा में किस हद तक सीधी भर्ती की जा सकती है, यह निर्धारित करते हुए यह भी कहा कि उच्च न्यायालयों द्वारा जल्द से जल्द उचित नियम बनाए जाने चाहिए। इसलिए, एक बार नियम लागू होने के बाद यह अभिनिर्धारित करना होगा कि उच्च न्यायालय से जो कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, वह उक्त नियमों का पालन करना होगा। हमने इस निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि नियम 7 और पैरा 9 (iv) के आधार पर, प्रथम प्रतिवादी उच्च न्यायालय को उच्च न्यायिक सेवा के पद पर चयन करते समय प्रक्रिया निर्धारित करने का पूरा अधिकार था और इस तरह की प्रक्रिया का पालन करना भी तर्कसंगत था। ”

उपरोक्त पैराग्राफ में, न्यायालय ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि शेट्टी आयोग की सिफारिशों को एक दिशानिर्देश माना जा सकता है और उच्च न्यायालय के पास न्यायिक अधिकारियों के चयन के लिए अपनी प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यक शक्ति निहित है। हमें दोहराना चाहिए कि एक संदर्भ भी दिया गया था अखिल भारतीय न्यायाधीशों (2002) का अनुच्छेद 28 जिसमें उच्च न्यायालय उपयुक्त नियम बनाएगा। इसके अलावा, शेट्टी आयोग ने स्वयं उल्लेख किया कि सिफारिश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन थी।

iv) इसी तरह, शशिधर रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य[16] के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि शेट्टी आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए नियमों द्वारा समर्थित

किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया कि जब सिफारिशें और नियम भिन्न होते हैं, तो वैधानिक नियमों का पालन किया जाना चाहिए। उसमें अपीलार्थी की शिकायत थी कि आंध्र प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा में जिला और सत्र न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त होने के लिए 35 वर्ष पूरे करने की आवश्यकता नहीं थी। इस संदर्भ में, न्यायालय ने शेट्टी आयोग की सिफारिशों का विश्लेषण निम्नानुसार कियाः

> "14. न्यूनतम आयु के संबंध में उक्त अवधारणा आयोग की रिपोर्ट से ही लाई गई है। आयोग की रिपोर्ट में दर्ज कारणों के लिए, आयोग का विचार था कि जिला और सत्र न्यायाधीश का पद, एक महत्वपूर्ण पद होने के नाते, जिसमें न केवल ईमानदारी और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, बल्कि परिपक्वता की भी आवश्यकता होती है, आयोग का विचार था कि 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं करने वाले व्यक्ति को उक्त पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि यह केवल आयोग द्वारा की गई एक सिफारिश या सुझाव था। यदि अनुशंसा या सुझाव नियमों द्वारा समर्थित नहीं है, तो इसे लागू नहीं किया जा सकता है। तत्काल मामले में, न्यूनतम आयु के संबंध में नियम मौन हैं। यह केवल अधिकतम आयु के बारे में बात करता है। इन परिस्थितियों में आयोग की रिपोर्ट में शामिल प्रावधानों को नियमों में नहीं पढ़ा जा सकता है। ये नियम वैधानिक हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत बनाए गए हैं। हमारी राय में, यदि आयोग द्वारा की गई सिफारिशें और वैधानिक नियम भिन्न हैं, तो भर्ती नियमों में शामिल प्रावधानों का पालन करना होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि जब सैयद टी. ए. नक्शबंदी मामले में इस अदालत के समक्ष ऐसा सवाल उठाया गया था [सैयद टी. ए. नक्शबंदी बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, (2003) 9 एस. सी. सी. 592:2003 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1151], इस न्यायालय ने यह भी

कहा था कि जब तक संबंधित भर्ती नियमों में उपयुक्त संशोधन नहीं किया जाता है ताकि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को शामिल किया जा सके, तब तक वैधानिक नियमों के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।

17. हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने शेट्टी आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को अनुचित महत्व देते हुए गलती की, विशेष रूप से जब नियमों में विचाराधीन पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 233 भी जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु के बारे में चुप है।

"

39. शेट्टी आयोग की सिफारिशों और प्रचलित नियमों के बीच अंतर-खेल पर उपरोक्त घोषणाओं के साथ, निम्नलिखित तार्किक कटौती निर्धारित की जा सकती हैः-

(i) सिफारिशों और नियमों के बीच विसंगति के मामले में, मौजूदा वैधानिक नियमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(ii) मौजूदा नियमों के अभाव में, उच्च न्यायालय को इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करना चाहिए।

40. पूर्णता के लिए, हम हालांकि स्पष्ट कर सकते हैं कि भले ही वैधानिक नियमों को अंतराल[17] को भरने के लिए पूरक किया जा सकता है, उच्च न्यायालय नियम 18 के विपरीत कार्य नहीं कर सकता है।

41. उपरोक्त समझ के साथ, आइए अब हम इस तर्क की जांच करें कि हेमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय[19] (संक्षेप में "हेमानी मल्होत्रा") और रमेश कुमार बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय[20] (के लिए) में निर्णय। संक्षिप्त में "रमेश कुमार"), इस प्रस्ताव के लिए अधिकारी हैं कि वाइवा वॉस के लिए कोई न्यूनतम अंक नहीं हो सकते हैं

क्योंकि शेट्टी आयोग की सिफारिशों को अखिल भारतीय न्यायाधीशों (2002) में स्वीकार कर लिया गया था। श्री ऋषभ संचेती, रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील अतिरिक्त रूप से यह तर्क दिया जाएगा कि महिंदर कुमार (एस. पी. आर. ए.) में निर्णय इनक्यूरियम के अनुसार है क्योंकि बाद का निर्णय होने के बावजूद, यह रमेश कुमार (एस. पी. आर. ए.) में पहले की प्रासंगिक टिप्पणियों का उल्लेख या विचार नहीं करता है। विद्वान वकील श्री पवनश्री अग्रवाल कहेंगे कि महेंद्र में लिए गए फैसलों के बीच एक द्वंद्व है। कुमार (ऊपर) और रमेश कुमार (ऊपर)। जबकि महेंद्र कुमार (ऊपर) शेट्टी आयोग की सिफारिशों को एक दिशानिर्देश होने का समर्थन करता है, रमेश कुमार (ऊपर) ने नोट किया कि सिफारिशों को इस न्यायालय द्वारा अखिल भारतीय न्यायाधीशों (2002) में स्वीकार कर लिया गया था।

42. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने निम्नलिखित पर भरोसा किया है हेमानी मल्होत्रा (ऊपर) का अनुच्छेदः

> “18. यह न्यायालय नोटिस करता है कि अखिल भारतीय न्यायाधीशों की सभा बनाम भारत संघ [(2002) 4 एस. सी. सी. 247:2002 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 508] उक्त निर्णय में बताए गए विभिन्न संशोधनों के अधीन, शेट्टी आयोग की अन्य सिफारिशों को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इसका मतलब है कि प्रत्यर्थी द्वारा वाइवा वॉयस टेस्ट में कट-ऑफ मार्क्स का निर्धारण इस अदालत के फैसले के अनुसार नहीं था। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी और इसलिए लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों को मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ने के बाद, याचिकाकर्ताओं का परिणाम घोषित किया जाना चाहिए था। जैसा कि पहले देखा गया था कि 16 रिक्त पदों को भरने के लिए अधिसूचित किया गया था और केवल पांच उम्मीदवारों ने

लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसलिए, यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों में जोड़ा गया होता, तो याचिकाकर्ताओं के नाम प्रत्यर्थी द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में पाए जाते। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं को आंशिक रूप से स्वीकार करना होगा। ”

43. उपरोक्त मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह थी कि दिल्ली उच्च न्यायालय सेवा परीक्षा 2006 में न्यूनतम कट-ऑफ अंक या वाइवा वॉस का कोई निर्धारण नहीं था। इसलिए यह मुद्दा न्यायालय के समक्ष यह था कि क्या चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों की आवश्यकता की शुरुआत, खेल खेले जाने के बाद खेल के नियमों को बदलने के बराबर होगी। यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने पैराग्राफ 15 में हेमानी मल्होत्रा (ऊपर) स्वयं टिप्पणी करते हैं किः

> “15. इसमें कोई संदेह नहीं है कि चयन को विनियमित करने वाले नियम बनाने वाला प्राधिकरण लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा दोनों के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित कर सकता है, लेकिन यदि चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं, तो संबंधित प्राधिकरण, चयन प्रक्रिया के दौरान या चयन प्रक्रिया के बाद एक अतिरिक्त आवश्यकता/योग्यता नहीं जोड़ सकता है कि उम्मीदवार को साक्षात्कार में न्यूनतम अंक भी प्राप्त करने चाहिए। इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि प्रत्यर्थी द्वारा मौखिक परीक्षा में न्यूनतम अंकों का निर्धारण अवैध था। ”
>
> [जोर दिया गया]

44. हेमानी मल्होत्रा (एस. पी. आर. ए.) में उपरोक्त निष्कर्ष साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करने वाले नियमों के अभाव में थे। यहाँ तथ्य काफी अलग हैं क्योंकि साक्षात्कार खंड में योग्यता अंकों को भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले अधिसूचित किया गया था। ऊपर चर्चा किए गए कानून के तय किए गए सिद्धांत के अनुरूप, सिफारिशों के साथ मौजूदा नियमों की विसंगति के मामले में, नियम प्रबल होंगे।

45. इसी तरह अन्य उद्धृत मामलों अर्थात रमेश कुमार (ऊपर उल्लिखित) में, न्यायालय ने कहा कि प्रासंगिक नियमों में किसी भी विपरीत प्रावधान के अभाव में, सक्षम प्राधिकारी लिखित और मौखिक दोनों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित कर सकते हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि विशिष्ट नियम वाइवा वॉस के लिए न्यूनतम अंकों का प्रावधान करते हैं, तो इसका कड़ाई से पालन अनिवार्य है। महत्वपूर्ण रूप से, निर्णय एक उम्मीदवार के समग्र बौद्धिक और व्यक्तिगत गुणों को सामने लाने में वाइवा वॉस टेस्ट के महत्व को भी स्पष्ट करता है। हेमानी मल्होत्रा (ऊपर) और रमेश कुमार (ऊपर) में महत्वपूर्ण रूप से बुनियादी मुद्दा यह था कि क्या चयन प्रक्रिया के बीच में खेल के नियमों को बदला जा सकता है। हालाँकि, वर्तमान मामलों में, रिट याचिकाकर्ता चयन प्रक्रिया शुरू होने से बहुत पहले खेल के नियमों यानी न्यूनतम अंकों के निर्धारण से अवगत थे। इस विशिष्ट विशेषता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस बिंदु पर, हम यह भी ध्यान दे सकते हैं कि वर्तमान रिट याचिकाओं को खेल के नियमों को बदलने के मुद्दे से संबंधित पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ[21] के मामले से हटा दिया गया था जो वर्तमान निर्णय के लिए आरक्षित है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अजीत कुमार सिन्हा ने इसे उचित रूप से स्वीकार किया है। इसलिए, यहाँ चुनौती खेल के नियमों को बदलने की नहीं है, बल्कि शेट्टी आयोग की सिफारिशों और अखिल भारतीय न्यायाधीश (2002) में निर्धारित कानून के निहितार्थ की है।

46. महेन्द्र कुमार (उपरोक्त) मामले में निर्णय से संबंधित विवाद पर, वर्तमान तथ्यों में सामंजस्य स्थापित करना संभव है। दोनों निर्णय अर्थात महेंद्र कुमार (ऊपर) और रमेश कुमार (ऊपर)। दोनों निर्णयों में महत्वपूर्ण रूप से इस बात पर जोर दिया जाता है कि मौजूदा वैधानिक नियमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रमेश कुमार (ऊपर) में प्रासंगिक अंश नीचे निकाला गया हैः

> "15. इस प्रकार, इस मुद्दे पर कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि यदि सांविधिक नियम चयन के किसी विशेष तरीके को निर्धारित करते हैं, तो उसी के अनुसार इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। यदि नियमों द्वारा कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है और कानून में कोई अन्य बाधा नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी चयन के लिए मानदंड निर्धारित करते समय परीक्षणों के लिए निर्धारित कर सकते हैं और लिखित परीक्षा के साथ-साथ मौखिक परीक्षा के लिए भी न्यूनतम मानदंड निर्दिष्ट कर सकते हैं। "

47. उपरोक्त पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि अदालतें वाइवा वॉस के लिए न्यूनतम योग्यता अंक तय कर सकती हैं। वर्तमान मामलों में, योग्यता अंकों के लिए प्रदान किए गए नियम और इस तरह उद्धृत निर्णय रिट याचिकाकर्ताओं के लिए कोई सहायता नहीं हो सकते हैं।

48. सलाम समरजीत सिंह बनाम मणिपुर उच्च न्यायालय इंफाल[22] में विभाजित निर्णय के निहितार्थ पर आगे विचार किया जाएगा। न्यायमूर्ति भानुमति ने अपने फैसले में कहा कि अखिल भारतीय न्यायाधीश (2002) वाइवा-वॉस टेस्ट के लिए न्यूनतम कट ऑफ अंकों के पहलू पर चुप हैं। अपने असहमत निर्णय में, न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह ने उक्त उप-मौन अवलोकन पर कोई असहमति व्यक्त नहीं की थी, लेकिन इसे भविष्य के मामले में निर्धारण के लिए खुला छोड़ दिया था। वहाँ फिर से, न्यायमूर्ति सिंह की

असहमति इस तथ्य पर आधारित थी कि भर्ती नियमों में न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित नहीं की गई थी और अदालत के प्रस्ताव द्वारा, साक्षात्कार के चरण से ठीक पहले, भर्ती प्रक्रिया के बीच में लाया गया था। हालाँकि यहाँ भर्ती प्रक्रिया में न्यूनतम कट-ऑफ के निर्धारण को जानकारी पटना उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय के तहत चयन प्रक्रिया शुरू होने से बहुत पहले उम्मीदवारों की जानकारी के लिए अधिसूचित किया गया था और इस विशिष्ट विशेषता को ध्यान में रखना होगा।

49. न्यायधीश शेट्टी आयोग का गठन न्यायिक अधिकारियों की सेवा स्थितियों में एकरूपता लाने के लिए किया गया था। आयोग द्वारा की गई सिफारिशें दिशा-निर्देशों की प्रकृति की हैं और उन्हें न्यायिक अधिकारियों की भर्ती को नियंत्रित करने वाले नियमों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अखिल भारतीय न्यायाधीशों (2002) में निर्णय के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि सर्वोत्तम संभव व्यक्ति का चयन सुनिश्चित करने के लिए साक्षात्कार खंड में योग्यता अंक निर्धारित करने के लिए पर्याप्त कोहनी की जगह उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, नियमों में न्यूनतम अंकों का निर्धारण उल्लंघन में नहीं पाया गया है अखिल भारतीय न्यायाधीशों में निर्णय (2002)।

मुद्दा संख्या ii) क्या वाइवा वॉस के लिए न्यूनतम अंकों का निर्धारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है?

50. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि वाइवा वॉस के लिए न्यूनतम अंकों का निर्धारण स्पष्ट रूप से मनमाना होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखा गया है जिन्होंने अनुच्छेद 14 के तहत परीक्षा का दायरा बढ़ाया है। [23] इस संदर्भ में, हमें ई. पी. रोयप्पा बनाम टी. एन. 24 राज्य मामले में पाँच-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय से

अक्सर उद्धृत अंश को याद करना चाहिए, जिसमें न्यायालय ने कथित रूप से भेदभावपूर्ण स्थानांतरण आदेश पर विचार करते हुए निम्नानुसार उल्लेख किया थाः

> " 85 .....सकारात्मक दृष्टिकोण से, समानता मनमानेपन के विरोधी है। वास्तव में, समानता और मनमानेपन कट्टर दुश्मन हैं; एक गणराज्य में कानून के शासन से संबंधित है जबकि दूसरा, एक पूर्ण सम्राट की सनक और सनक से संबंधित है। जहाँ कोई कार्य मनमाना है, वहाँ यह निहित है कि यह राजनीतिक तर्क और संवैधानिक कानून दोनों के अनुसार असमान है और इसलिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, और यदि यह सार्वजनिक रोजगार से संबंधित किसी भी मामले को प्रभावित करता है, तो यह अनुच्छेद 16 का भी उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 और 16 राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन पर प्रहार करते हैं और निष्पक्षता और व्यवहार की समानता सुनिश्चित करते हैं। वे चाहते हैं कि राज्य को समान रूप से स्थित सभी लोगों के लिए समान रूप से कारवाई करनी चाहिए जो लागू वैध प्रासंगिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए और इसे किसी भी बाहरी या अप्रासंगिक विचारों द्वारा निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह समानता से इनकार होगा। जहां राज्य की कार्रवाई के लिए कार्यात्मक कारण, जैसा कि मन के तंत्र से प्रेरित उद्देश्य से अलग है, वैध और प्रासंगिक नहीं है, लेकिन बाहरी है और अनुमेय विचारों के क्षेत्र से बाहर है, यह शक्ति का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग होगा और जो अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा प्रभावित होता है। शक्ति और मनमानेपन का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग एक ही बुराई से निकलने वाले अलग-अलग घातक विकिरण हैंःवास्तव में बाद वाला पहले वाले को समझता है। दोनों अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा बाधित हैं। "

51. अनुच्छेद 14 के शब्दों में गैर-मनमानी के सिद्धांत पर टिप्पणी करते हुए, पांच न्यायाधीशों की एक अन्य पीठ पी. एन. भगवती के माध्यम से बोल रही है। जे. अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब सहरावर्दी[25], (संक्षेप में "अजय हसिया") उन्होंने निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां कींः

> "16. ...इसलिए अब यह अच्छी तरह से तय किया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 14 जिस पर हमला करता है वह मनमाना है क्योंकि कोई भी (संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) कार्रवाई जो मनमाना है, उसमें अनिवार्य रूप से समानता का निषेध शामिल होना चाहिए। न्यायालय द्वारा विकसित वर्गीकरण का सिद्धांत अनुच्छेद 14 की व्याख्या नहीं है और न ही यह उस अनुच्छेद का उद्देश्य और अंत है। यह केवल यह निर्धारित करने के लिए एक न्यायिक सूत्र है कि क्या विचाराधीन विधायी या कार्यकारी कार्रवाई मनमाना है और इसलिए समानता से इनकार का गठन करती है। यदि वर्गीकरण उचित नहीं है और ऊपर उल्लिखित दो शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो विवादित विधायी या कार्यकारी कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमाना होगी और अनुच्छेद 14 के तहत समानता की गारंटी का उल्लंघन किया जाएगा। इसलिए जहां कहीं भी राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन होता है, चाहे वह अनुच्छेद 12 के तहत विधायिका की हो या कार्यपालिका की या किसी "प्राधिकरण" की, अनुच्छेद 14 तुरंत कार्रवाई में आता है और ऐसी राज्य कार्रवाई को रद्द कर देता है। वास्तव में, तर्कसंगतता और गैर-मनमानी की अवधारणा पूरी संवैधानिक योजना में व्याप्त है और एक सुनहरा धागा है जो संविधान के पूरे ताने-बाने में चलता है। "

52. शायरा बानो बनाम भारत संघ[26] में, उदाहरणों की एक लंबी पंक्ति की जांच करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक कानून को स्पष्ट रूप से मनमाना होने के लिए भी खारिज किया जा सकता है, अगर वह "तर्कहीन, मज़बूत" और/या पर्याप्त

निर्धारण सिद्धांत के बिना है। यह सिद्धांत इस न्यायालय के अन्य निर्णयों में स्पष्ट मनमानेपन को उजागर किया गया है। अब जिस मुद्दे की जांच की जानी है, वह यह है कि क्या वाइवा वॉस टेस्ट के लिए योग्यता अंक निर्धारित करने वाले नियमों के लिए मनमानेपन का दोष आकर्षित होता है।

53. वाइवा वॉयस के लिए न्यूनतम अंकों के निर्धारण के लिए रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई चुनौती असामान्य नहीं है और उदाहरणों से पता चलता है कि पद की प्रकृति और वाइवा वॉयस को दिए गए महत्व की सीमा पर बहुत अधिक परिवर्तन होता है। वर्तमान मामलों के लिए, उच्च न्यायपालिका, विशेष रूप से जिला न्यायाधीशों के लिए चयन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले बिहार नियम, 1951 और गुजरात नियम, 2005 के नियम 8 (3), जो सिविल और जिला न्यायाधीशों दोनों की भर्ती से संबंधित है, के बीच अंतर पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होगी।

54. उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति से संबंधित बिहार नियम, 1951 के प्रासंगिक खंड तैयार संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैंः

> “10. उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए तभी अर्हता प्राप्त करेगा जब वह प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक और लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा। बशर्ते कि यदि योग्य उम्मीदवारों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो उच्च न्यायालय न्यायपालिका के हित में योग्यता अंकों में कुल मिलाकर छूट दे सकता है, लेकिन यह छूट कुल मिलाकर 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
>
> 11. उम्मीदवारों को साक्षात्कार में 50 में से कम से कम 10 अंक प्राप्त करने चाहिए।

12. नियुक्ति के लिए विचार करने से पहले उम्मीदवार को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में उत्तीर्ण होना चाहिए। ”

55. न्यायिक सेवा में चयन के लिए साक्षात्कार के महत्व को न्यायमूर्ति ओ. चिनप्पा रेड्डी जे. की राय से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। लीला धार बनाम राजस्थान राज्य में[28]:

“5. ...अब यह अच्छी तरह से माना जाता है कि एक लिखित परीक्षा एक उम्मीदवार के ज्ञान और बौद्धिक क्षमता का आकलन करती है, एक साक्षात्कार परीक्षा एक उम्मीदवार के समग्र बौद्धिक और व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए मूल्यवान है। जबकि एक लिखित परीक्षा का साक्षात्कार परीक्षा की तुलना में कुछ विशिष्ट लाभ है, अभी तक कोई लिखित परीक्षा नहीं है जो उम्मीदवार की पहल, सतर्कता, संसाधन, निर्भरता, सहयोगात्मकता, स्पष्ट और तार्किक प्रस्तुति की क्षमता, चर्चा में प्रभावशीलता, बैठक में प्रभावशीलता और दूसरों के साथ व्यवहार, अनुकूलनशीलता, निर्णय, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता, बौद्धिक और नैतिक अखंडता का मूल्यांकन कर सकती है। इनमें से कुछ गुणों का मूल्यांकन, शायद कुछ हद तक त्रुटि के साथ, एक साक्षात्कार परीक्षण द्वारा किया जा सकता है, जो साक्षात्कार बोर्ड के गठन पर निर्भर करता है। ”

56. उपरोक्त दृष्टिकोण का बाद इस न्यायालय के निर्णयों[29] द्वारा लगातार समर्थन किया गया है। विशेष रूप से तान्या मलिक बनाम उच्च न्यायालय महापंजीयक में[30] जिला न्यायाधीश के पद पर भर्ती के संदर्भ में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करना न केवल वांछनीय है, बल्कि आवश्यक भी है। हाल ही में कविता खंबा (एस. पी. आर. ए.) मामले में 3-न्यायाधीशों की पीठ ने जिला

न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता को बरकरार रखा। न्यायपालिका के कनिष्ठ स्तर और उच्च स्तर पर न्यायिक नियुक्तियों के बीच एक संक्षिप्त अंतर करते हुए, इस न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के माध्यम से निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> "44....ऐसे मामलों में साक्षात्कार सेवा की बहुत सीमा पर आयोजित नहीं किया जा रहा है, जबकि सबसे कनिष्ठ स्तर पर भर्ती की जा रही है। बल्कि, साक्षात्कार जिला न्यायपालिका में एक वरिष्ठ पद, एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस तरह अधिकारियों से, उनके पूर्व अनुभव के आधार पर, उनकी लंबे वर्षों की सेवा से उत्पन्न न्यायिक कार्य में प्रवीणता प्रदर्शित करने की अपेक्षा की जानी चाहिए। उस वर्ग के अधिकारियों के लिए साक्षात्कार का उद्देश्य एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की भूमिका निभाने के लिए आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता के संदर्भ में अधिकारी का आकलन करना है। नतीजतन, यदि उच्च न्यायालय ऐसा करता है, तो लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा दोनों में न्यूनतम पात्रता या कट-ऑफ की आवश्यकता को अलग-अलग लागू करने का एक उचित और वैध आधार होगा। "

57. भर्ती प्रक्रिया को उच्च न्यायपालिका में पदों पर नियुक्ति के लिए न केवल उम्मीदवार की बुद्धि बल्कि उनके व्यक्तित्व की भी परीक्षा लेनी चाहिए। रिट याचिकाकर्ताओं ने अजय हसिया (ऊपर) के फैसले पर बहुत भरोसा किया है, जहां यह दावा किया गया है कि साक्षात्कार के लिए कुल अंकों के 15 प्रतिशत से अधिक का प्रावधान मनमाना और संवैधानिक रूप से अमान्य है। अजय हसिया (ऊपर) में चुनौती शैक्षणिक वर्ष 1979-80 के लिए क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज में किए गए प्रवेश की वैधता के लिए थी। कुल 150 अंकों में से 50 अंक साक्षात्कार के लिए निर्धारित किए गए थे। अनुमेय परीक्षण

के रूप में वाइवा वॉस की वैधता पर टिप्पणी करते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

> "लेकिन, इन सभी आलोचनाओं के बावजूद, मौखिक साक्षात्कार विधि उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए एक पूरक परीक्षा के रूप में प्रचलित है, जहां व्यक्तिगत लक्षणों का परीक्षण आवश्यक माना जाता है। व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण के रूप में इसकी प्रासंगिकता को इस न्यायालय के कई निर्णयों में मान्यता दी गई है जो हम पर बाध्यकारी हैं। "

58. यह आगे नोट किया गया था किः

> "मौखिक साक्षात्कार परीक्षण निस्संदेह उम्मीदवारों की क्षमता और क्षमता का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए बहुत संतोषजनक परीक्षण नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत विशेषताओं और लक्षणों को मापने के लिए किसी भी बेहतर परीक्षण के अभाव में, मौखिक साक्षात्कार परीक्षण को वर्तमान स्तर पर तर्कहीन या अप्रासंगिक नहीं माना जाना चाहिए, हालांकि यह व्यक्तिपरक है और पहली धारणा पर आधारित है, इसका परिणाम कई अनिश्चित कारकों से प्रभावित होता है और यह दुरुपयोग करने में सक्षम है। हालाँकि, हम यह बताना चाहेंगे कि कॉलेज में प्रवेश के मामले में या यहाँ तक कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में, वर्तमान में आयोजित मौखिक साक्षात्कार परीक्षा को एक विशेष परीक्षा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग केवल एक अतिरिक्त या पूरक परीक्षा के रूप में किया जा सकता है और इसके अलावा, यह देखने के लिए बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए कि

मौखिक साक्षात्कार परीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति उच्च निष्ठा, क्षमता और योग्यता वाले व्यक्ति हैं। ”

59. अंततः यह निष्कर्ष निकाला गया कि साक्षात्कार खंड के लिए 33.5% के रूप में उच्च प्रतिशत प्रदान करना, मनमानेपन के साथ प्रवेश प्रक्रिया को संक्रमित कर रहा था। वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए, अजय हसिया (ऊपर) में उपरोक्त उक्ति के उल्लंघन पर रिट याचिकाकर्ताओं के तर्क का लीला धार (ऊपर) में पर्याप्त उत्तर दिया गया है, जहां तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने राजस्थान न्यायिक सेवा के लिए मुन्सिफ़ों के चयन के मुद्दे पर विचार किया। चयन लिखित परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना था, जिसमें वाइवा वॉस खंड के लिए 25 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए थे। अजय हसिया (ऊपर) में फैसले को अलग करते हुए, जो कॉलेज प्रवेश के संदर्भ में था, लीला धार (ऊपर) में अदालत ने प्रासंगिक रूप से निम्नलिखित राय दीः

> “न्यायालय की टिप्पणियां मुख्य रूप से कॉलेजों में प्रवेश की समस्या के संबंध में की गई थीं, जहां स्वाभाविक रूप से, शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रमुख महत्व दिया जाना चाहिए। पहले निकाले गए मार्ग में आने वाले "या यहां तक कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में" शब्दों और भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में साक्षात्कार परीक्षा के लिए आवंटित अंकों के संदर्भ का उद्देश्य कोई व्यापक, सामान्य नियम निर्धारित करना नहीं था कि वही सिद्धांत जो कॉलेजों में प्रवेश के मामले में लागू होता है, वह सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के मामले में भी लागू होता है। सार्वजनिक रोजगार से संबंधित अवलोकन अस्पष्ट था क्योंकि यह मामला उस मामले में न्यायालय के विचार के लिए नहीं आता था। न ही हम यह समझते हैं कि न्यायालय ने अपने अवलोकन के किसी भी व्यापक निर्माण का इरादा किया था। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि साक्षात्कार परीक्षा को दिया जाने वाला महत्व उस सेवा की

आवश्यकता पर निर्भर करना चाहिए जिसके लिए भर्ती की जाती है, भर्ती के लिए उपलब्ध स्रोत सामग्री, साक्षात्कार बोर्ड की संरचना और इसी तरह के कई कारक। आम तौर पर लोक सेवाओं में भर्ती को संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है और अगर हम चयन की उपयुक्त विधि और विभिन्न परीक्षणों के साथ जोड़ा जाने वाला सापेक्ष वजन को फिर से निर्धारित करने का प्रयास करते हैं तो हम एक ऐसे कार्य को हड़प लेंगे जो हमारा नहीं है।

60. लीला धार (ऊपर) में उपरोक्त राय यह स्पष्ट करती है कि अजय हसिया (ऊपर) में अनुपात, कॉलेज प्रवेश के संदर्भ में, न्यायिक रिक्तियों के लिए भर्ती पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डाल सकता है, जहां मौखिक साक्षात्कार न्यायिक पदों के लिए उम्मीदवार के व्यक्तित्व और क्षमता का परीक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

61. आइए अब हम गुजरात नियम, 2005 के नियम 8 (3) की संवैधानिकता पर सवाल उठाने वाली विशिष्ट चुनौती की जांच करें जो जिला न्यायाधीशों और सिविल न्यायाधीशों दोनों से संबंधित है। नियम 8 (3) इस प्रकार हैः

> "जिला न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में भर्ती के लिए आयोजित वाइवा-वॉयस में न्यूनतम योग्यता अंक चालीस प्रतिशत (40 प्रतिशत) अंक होंगे। "

62. अनुच्छेद 14 के तहत गुजरात नियम, 2005 के नियम 8 (3) को निरस्त करने के लिए, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मेधावी और गैर-मेधावी उम्मीदवारों के बीच एक वर्गीकरण बनाने की मांग की जाती है क्योंकि जिन मेधावी उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की है, वे सफल नहीं हो सकते हैं क्योंकि साक्षात्कार समिति किसी उम्मीदवार को उनके व्यक्तिपरक मूल्यांकन के

आधार पर समान अंकों से नीचे का पुरस्कार दे सकती है। दूसरा तर्क हाशिए की पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक समान अवसर की अनुपस्थिति के मुद्दे पर है जो यह सुझाव देता है कि ऐसे उम्मीदवार नुकसान में होंगे। जवाब में गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उद्देश्य सर्वोत्तम संभावित उम्मीदवारों का चयन करना है और साक्षात्कार आयोजित करने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश निश्चित रूप से एक उम्मीदवार की वास्तविक क्षमता का परीक्षण कर सकते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

63. यहाँ एक प्रासंगिक प्रश्न यह है कि जिन लोगों ने लिखित परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए थे, क्या उन्हें स्वयं "मेधावी" श्रेणी में माना जा सकता है?यह एक विवादास्पद मुद्दा है क्योंकि लिखित परीक्षा के लिए उच्च अंक अपने आप में एक उम्मीदवार की योग्यता और उपयुक्तता का निर्धारण नहीं करते हैं। प्रदर्शन उम्मीदवार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पूंजी पर भी निर्भर करेगा। कोचिंग संस्थान, गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा, वित्तीय स्थिरता, समय और लचीलापन, नेटवर्किंग के अवसर, मार्गदर्शन और प्रासंगिक अध्ययन सामग्री तक पहुंच जैसे संसाधनों तक पहुंच महत्वपूर्ण कारक हैं जो लिखित परीक्षा में प्रदर्शन में स्पष्ट रूप से योगदान करते हैं। इस संदर्भ में, बी. के. पवित्रा बनाम भारत संघ[31] में पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ प्रकाश डालने वाली हैं जहाँ निम्नलिखित परिच्छेद में "योग्यता" और "दक्षता" के पहलुओं पर चर्चा की गई थीः-

> “134. यह अच्छी तरह से तय है कि समाज में मौजूदा असमानताएं विशेषाधिकार प्राप्त उम्मीदवारों के पक्ष में भेदभाव करने वाली एक तटस्थ प्रणाली को जन्म दे सकती हैं। जैसा कि मार्क गैलांटर ने नोट किया है, प्रतियोगी परीक्षाओं में परिणाम देने के लिए तीन व्यापक प्रकार के संसाधन आवश्यक हैं जो योग्यता के संकेतक के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं।

ये हैंः—...

(क) आर्थिक संसाधन (पूर्व शिक्षा, प्रशिक्षण, सामग्री, काम से स्वतंत्रता आदि के लिए);

(ख) सामाजिक और सांस्कृतिक संसाधन (संपर्कों के नेटवर्क, विश्वास, मार्गदर्शन और सलाह, जानकारी, आदि।); और

(ग) आंतरिक क्षमता और कड़ी मेहनत। प्रतिस्पर्धी समानताएँःभारत में कानून और पिछड़े वर्ग, (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली 1984), देशपांडे एस. द्वारा उद्धृत, समावेश बनाम उत्कृष्टताःजाति और भारतीय उच्च शिक्षा में उचित पहुंच का निर्माण, 40:1 समाजशास्त्र की दक्षिण अफ्रीकी समीक्षा 127-147।]

135. पहले दो मानदंड स्पष्ट रूप से किसी उम्मीदवार के अपने प्रयासों के उत्पाद नहीं हैं, बल्कि वे संरचनात्मक स्थितियां हैं जिनमें वे पैदा होते हैं। ”

64. जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, योग्यता के एकमात्र निर्धारक के रूप में प्रतियोगी परीक्षाओं या लिखित परीक्षाओं पर निर्भरता को तेजी से अस्वीकार किया जा रहा है। दार्शनिक माइकल सैंडल की पुस्तक, "द टायरेनी ऑफ मेरिट" से वाक्यांश को उधार लेने के लिए, सफल उम्मीदवार अक्सर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, जाति, लिंग और अन्य संरचनात्मक असमानताओं जैसे कारकों को अवसरों और परिणामों को कैसे आकार दे सकते हैं, इसकी अनदेखी करते हुए "योग्यतापूर्ण अहंकार"[32] की भावना महसूस करते हैं।

65. लिखित परीक्षा संभवतः व्यक्ति की क्षमताओं और क्षमता के पूर्ण वर्णक्रम को नहीं पकड़ सकती है। एक साक्षात्कार भी प्रदान कर सकता है हाशिए पर पड़े उम्मीदवारों के लिए अपनी प्रतिभा को उन तरीकों से प्रदर्शित करने का माध्यम जो एक लिखित

परीक्षा संभवतः अनुमति नहीं देती है। हालाँकि, यहाँ एक चेतावनी आवश्यक हो सकती है कि अंग्रेजी बोलने वाले शहरी वातावरण से आने वाले उम्मीदवारों के पास भाषाई प्रवाह और सांस्कृतिक मानदंडों के साथ परिचितता हो सकती है जो आमतौर पर साक्षात्कार से जुड़े होते हैं और इसलिए वे सापेक्ष आसानी के साथ वाइवा वॉस खंड को नेविगेट करने की संभावना रखते हैं। इसके विपरीत, हाशिए पर पड़े समुदायों के उम्मीदवारों को शहरी सेटिंग्स के संपर्क में न आने के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लिंग, धर्म, जाति आदि के आधार पर सचेत और अचेतन पूर्वाग्रह से यह और बढ़ जाता है। लेकिन क्या हम भूसी से अनाज को अलग करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा गठित साक्षात्कार पैनल के सदस्यों की आंतरिक क्षमता को नजरअंदाज कर सकते हैं?यह न्यायालय यह मानना चाहेगा कि साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान उन लोगों के लिए एक समान अवसर प्रदान कर सकते हैं जो एक वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, ताकि साक्षात्कारकर्ताओं की वास्तविक योग्यता और क्षमता का आकलन किया जा सके। इसका समाधान यह है कि साक्षात्कार करने वाले सदस्य साक्षात्कार की प्रक्रिया में पूर्वाग्रह को कम करने के लिए जागरूक और संवेदनशील हों। हालांकि, पूर्वाग्रह की आशंका एक नियम को रद्द करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।

66. जैसा कि पूर्ववर्ती उदाहरणों से देखा जा सकता है, इस न्यायालय द्वारा केवल वाइवा-वॉस खंड को अधिक महत्व दिए जाने को अस्वीकार कर दिया गया है, लेकिन उचित योग्यता कट-ऑफ अंक 33 के निर्धारण को भेदभावपूर्ण नहीं माना जाता है। किसी भी मामले में, प्रशासनिक कानूनी उपाय हमेशा उन मामलों में राहत पाने के लिए उपलब्ध होते हैं जहां सत्ता का दुरुपयोग देखा जाता है। जब बिहार भर्ती के लिए 20 प्रतिशत और गुजरात भर्ती के लिए 40 प्रतिशत की न्यूनतम कट-ऑफ को ध्यान में रखा जाता है, तो उन्हें उच्च सीमा प्रदान करने के लिए नहीं माना जा सकता है यदि कोई यह

ध्यान रखता है कि भर्ती न्यायिक अधिकारियों के चयन के लिए है। इस संदर्भ में, गुजरात नियम, 2005 के नियम 8 (5) में निर्धारित वाइवा वॉस का उद्देश्य ध्यान देने योग्य है और इसे निकाला गया हैः

> "(5) वाइवा-वॉस टेस्ट (साक्षात्कार) का उद्देश्य कैडर के लिए उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता, कानून का ज्ञान, स्पष्ट और तार्किक व्याख्या, निर्णय संतुलन, कौशल, दृष्टिकोण, नैतिकता, आत्मसात करने की शक्ति, संचार की शक्ति, चरित्र और बौद्धिक गहराई और इसी तरह का आकलन करके कैडर के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करना है। "

67. उपरोक्त से पता चलता है कि प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक उचित और प्रत्यक्ष संबंध है अर्थात सुव्यवस्थित न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति। न्यूनतम कट ऑफ के निर्धारण को भी इस तरह की प्रकृति का नहीं माना जाता है कि यह अतार्किकता का संकेत देता है, या मज़बूत और/या बिना किसी पर्याप्त निर्धारण सिद्धांत के था। यह असमान प्रतीत नहीं होता है ताकि "मेधावी" उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जैसा कि तर्क दिया गया है। यह निश्चित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट रूप से मनमाना, या तर्कहीन या उल्लंघन नहीं है। न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए, आदर्श रूप से प्रयास न केवल उम्मीदवार की बुद्धि बल्कि उनके व्यक्तित्व का भी परीक्षण करने का होना चाहिए। एक साक्षात्कार एक उम्मीदवार के सार-उनके व्यक्तित्व, जुनून और क्षमता का खुलासा करता है। जबकि लिखित परीक्षा ज्ञान को मापती है, साक्षात्कार चरित्र और क्षमता को प्रकट करता है। इसलिए, विशेष रूप से एक न्यायिक अधिकारी के रूप में एक जिम्मेदार पद की मांग करने वाले व्यक्ति को केवल कागज पर उनके प्रदर्शन के आधार पर

शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनकी स्पष्ट करने और संलग्न करने की क्षमता के आधार पर भी चुना जाना चाहिए जो अदालत में पीठासीन अधिकारी की भूमिका के लिए उनकी उपयुक्तता को प्रदर्शित करेगा। दूसरे शब्दों में, प्रतिकूल मुकदमेबाजी का निर्णय लेने के लिए अदालत की अध्यक्षता करने के लिए उम्मीदवार की क्षमता और क्षमता का भी साक्षात्कार के दौरान सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

68. उपरोक्त मापदंडों पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि संबंधित भर्ती नियम असंवैधानिक हैं। यहाँ यह भी देखा जा सकता है कि अनुच्छेद 14 के तहत परीक्षण में विफल होने के लिए रिट याचिकाकर्ताओं की वैध अपेक्षा का कोई उल्लंघन नहीं है। शिवानंद सी. टी. बनाम केरल उच्च न्यायालय[34] में, जिसका उल्लेख किया गया है, तथ्यात्मक पृष्ठभूमि है। अलग था। केरल राज्य उच्च न्यायिक सेवा नियम 1961 यह निर्धारित किया गया है कि बार से सीधी भर्ती "उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा और मौखिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों/ग्रेड के आधार पर होगी। " वाइवा वॉयस के संचालन के बाद ही उच्च न्यायालय ने योग्यता मानदंड के रूप में न्यूनतम कट ऑफ करने का फैसला किया। विशिष्टता यह है कि न ही केरल राज्य उच्च न्यायिक सेवाओं के प्रावधान विशेष नियम, 1961 और न ही परीक्षा योजना या भर्ती अधिसूचना में वाइवा वॉस के लिए कोई कट-ऑफ निर्धारित की गई थी। इसलिए, यह उस संदर्भ में था कि न्यायालय ने माना कि न्यूनतम कट-ऑफ अंक संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उम्मीदवारों की मूल वैध अपेक्षा को विफल करने के लिए स्पष्ट रूप से मनमाना था। इसलिए, उद्धृत मामले का वर्तमान मामलों में कोई उपयोग नहीं हो सकता है जहां चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले वाइवा वॉस में कट ऑफ मार्क्स को अधिसूचित किया गया था।

मुद्दा सं. iii) क्या बिहार में चयन प्रक्रिया को बिहार चयन प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं द्वारा बताए गए अंकों और सुधारात्मक कदमों के संयम को देखते हुए दूषित किया गया है?

69. इसके लिए, यह देखने की आवश्यकता है कि क्या वैधानिक नियमों के उल्लंघन, पूर्वाग्रह, दुर्भावनापूर्ण या धोखाधड़ी के आरोप साबित हुए हैं। [35] इस संबंध में, अशोक कुमार यादव बनाम हरियाणा राज्य[36] मामले में चार न्यायाधीशों की पीठ, संपूर्ण चयन प्रक्रिया को अमान्य करने के लिए सीमा पर चर्चा निम्नानुसार की गईः

"21. ...लेकिन संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता है और हम इस आधार पर किए गए चयन को खारिज नहीं कर सकते हैं कि मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों की योग्यता का मूल्यांकन मनमाना हो सकता है। यह इंगित करना आवश्यक है कि न्यायालय साक्षात्कार निकायों द्वारा दिए गए अंकों पर निर्णय नहीं दे सकता है जब तक कि यह साबित या स्पष्ट नहीं हो जाता है कि अंकन स्पष्ट रूप से और निर्विवाद रूप से मनमाना है या तिरछे उद्देश्यों से प्रभावित है। यह केवल तभी है जब मूल्यांकन स्पष्ट रूप से मनमाना है या मनमानेपन का जोखिम इतना अधिक है कि एक उचित व्यक्ति मनमानेपन को अपरिहार्य मानेगा, कि वाइवा वॉस परीक्षण में अंकों के मूल्यांकन को मनमानेपन के दुष्प्रभाव से पीड़ित माना जा सकता है। "

70. उपरोक्त सिद्धांत द्वारा निर्देशित, विज्ञापन जारी करने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए कदमों पर विचार किया जाएगा, जैसा कि नीचे संक्षेप में पटना उच्च न्यायालय के अतिरिक्त हलफनामे में उल्लेख किया गया है।

i) प्रारंभिक परीक्षा 22.3.2015 पर आयोजित की गई थी। 6,771 उम्मीदवार उसी के लिए उपस्थित हुए।

ii) मुख्य परीक्षा 12.7.2015 पर आयोजित की गई थी और इसके लिए 1000 से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए थे।

iii) हलफनामे में कहा गया है कि केवल 15 उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में योग्यता अंक प्राप्त किए हैं यानी 55 प्रतिशत से अधिक। हालांकि, श्री गौतम पटना उच्च न्यायालय के विद्वान वकील नारायण ने स्पष्ट किया है कि यह एक टंकण संबंधी त्रुटि है और वास्तव में केवल 3 उम्मीदवारों ने योग्यता अंक प्राप्त किए थे। यह आर. टी. आई. जवाब दिनांक 10.2.2017 के अनुरूप है।

iv) रिक्तियों को भरने के लिए, उच्च न्यायालय की चयन और नियुक्ति समिति ने यादृच्छिक रूप से प्रत्येक पेपर की 20 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की। यह निर्णय लिया गया कि संयम की आवश्यकता है। तदनुसार, उच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों वाली चयन और नियुक्ति समिति ने अपनी दिनांकित आई. डी. 1 की बैठक में पेपर I में 4 प्रतिशत और पेपर II में 6 प्रतिशत अंक जोड़कर मॉडरेशन का प्रस्ताव रखा।

v) संयम के बावजूद, केवल कुछ उम्मीदवारों ने कुल मिलाकर 55 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए। इसके बाद, पूर्ण न्यायालय ने 1951 के नियमों के परिशिष्ट सी के खंड 10 के प्रावधान के तहत कुल अंकों में 5 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया।

vi) अंकों में 50 प्रतिशत की छूट के बाद, 81 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में योग्य पाया गया और परिणाम 22.1.2016 को अपलोड किए गए।

vii) लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों के लिए साक्षात्कार उच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों के बोर्ड द्वारा 19.2.2016,20.2.2016,22.2.2016 और 23.2.2016 पर आयोजित किए गए थे। आखिरकार, केवल 9 उम्मीदवार साक्षात्कार में कुल 50 अंकों में से 10 या उससे अधिक अंक प्राप्त कर सके। उक्त 9 व्यक्तियों

को पूर्ण न्यायालय की मंजूरी पर बिहार सरकार द्वारा 17.5.2016 को नियुक्त किया गया था।

71. बिहार रिट याचिका में नोटिस जारी होने के बाद, संबंधित उच्च न्यायालय के अधिकारियों ने प्रतिक्रिया तैयार करते समय, डिकोडिंग, सारणीकरण और अंकों के मिलान के दौरान विसंगतियों को देखा और चयन डेटा के पुनः सत्यापन की व्यवस्था की। इसके बाद, समिति के अध्यक्ष द्वारा पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से निम्नलिखित निर्देश जारी किए गएः

"गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए समिति उपलब्ध नहीं है। माननीय ए. सी. जे. के साथ फोन पर इस मामले पर चर्चा की। एक गंभीर चूक होने के कारण, निम्नलिखित कदम तुरंत उठाए जाने की आवश्यकता हैः

1) निबंधक (नियु०), की व्यक्तिगत देखरेख में, सिनियर प्रोग्रामर नितेश नये सिरे से डिकोडिंग, मिलान और सारणीकरण करेंगे। किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर महानिबंधक से परामर्श किया जाएगा। नया सारणीकरण तैयार करें, खामियों की पहचान करें, रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

2) महानिबंधक यह पता लगाने के लिए जांच करेंगे कि खामियां कहां थीं और इसके परिणामस्वरूप कौन जिम्मेदार था। इस रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने पर, इन खामियों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना। महापंजीयक कारण दर्शाएँगे और भाई अजय कुमार त्रिपाठी अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। जैसे ही वह उपलब्ध हों, माननीय ए. सी. जे. के सामने पेश हों। अत्यधिक तात्कालिकता और गोपनीयता के साथ निपटाए जाने वाले मामले। "

72. अभिलेख के विस्तृत सत्यापन के बाद, यह पाया गया कि 3 और उम्मीदवारों ने जिनके रोल नं० क्रमशः 1111006603,1111006636 और 1111006667 थे। वाइवा

वॉस के उद्देश्य से लिखित परीक्षा में योग्यता अंक प्राप्त किए थे। यह भी पाया गया कि 4 उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में योग्यता अंक प्राप्त नहीं किए थे, हालांकि उन्हें पहले योग्य दिखाया गया था। इसलिए, आई. डी. 1 पर एक शुद्धिपत्र जारी किया गया जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने 4 अयोग्य उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया और योग्यता अंक प्राप्त करने वाले वाइवा-वॉस के लिए 3 अन्य उम्मीदवारों को भी बुलाया। 3 उम्मीदवारों का साक्षात्कार 19.7.2016 पर आयोजित किया गया था। हालांकि, उनमें से कोई भी योग्यता प्राप्त नहीं कर सका।

73. वरिष्ठ वकील श्री अजीत सिन्हा ने तर्क दिया था कि ये अनियमितताएं इतनी गंभीर हैं कि यह पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित कर देगी। यह स्वीकार करते हुए कि मोडरेशन से रिट याचिकाकर्ताओं को लाभ हुआ, फिर भी यह तर्क दिया जाता है कि दोषपूर्ण प्रक्रिया को इस न्यायालय को बिहार में चयन प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए राजी करना चाहिए। इसके विपरीत, पटना उच्च न्यायालय के विद्वान वकील श्री गौतम नारायण का तर्क है कि अनुक्रमांक में विसंगतियां स्वयं उम्मीदवारों की गलती के कारण थीं। जहां तक मोडरेशन का संबंध है, श्री नारायण ने हमारे समक्ष एक चार्ट प्रस्तुत किया जिसमें उम्मीदवारों द्वारा मोडरेशन से पहले और बाद में प्राप्त अंकों को दिखाया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि यह रिट याचिकाकर्ताओं के लाभ के लिए है।

74. क्या अंकों का मॉडरेशन कानूनी रूप से अनुमत था, इसके लिए प्रासंगिक नियमों और विज्ञापन के संदर्भ की आवश्यकता होगी। बिहार नियम, 1951 के परिशिष्ट सी का प्रासंगिक खंड 13 नीचे दिया गया हैः

> “13. उच्च न्यायालय, पटना की स्थायी समिति किसी भी संदेह और कठिनाई के मामले में आदेश/निर्देश जारी कर सकती है "2015 के विज्ञापन का पैरा 10 इस

प्रकार है:"10. उच्च न्यायालय के पास न्यायपालिका के हित में उपरोक्त नियमों और शर्तों में कोई छूट या छूट देने की शक्ति होगी। "

75. उपरोक्त यह स्पष्ट करता है कि उच्च न्यायालय को न्यायपालिका के हित में स्पष्टीकरण, छूट और यहां तक कि छूट प्रदान करने के लिए आवश्यक शक्तियां निहित की गई हैं। "छूट" शब्द के साथ-साथ किसी भी "कठिनाई" के मामले में आदेश/निर्देश जारी करने की सामान्य शक्ति, हमारे विचार में साक्षात्कार परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को प्रदान करने के लिए संयम की प्रक्रिया की अनुमति देगी। विज्ञापन के पैरा 10 के साथ पठित बिहार नियमों के परिशिष्ट सी का खंड 13 चयन प्रक्रिया में कठिनाइयों को दूर करने के लिए उच्च न्यायालय को पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है। यह किसी का मामला नहीं है कि सुधारात्मक उपाय उचित नहीं थे। इसके अलावा, अपनाई गई प्रक्रिया नियमों के अनुरूप है।

76. एक मोडरेशन अभ्यास में, अंकों का जोड़ और/या कटौती की परिकल्पना की गई है। संजय सिंह बनाम यूपी लोक सेवा मामले में यह अदालत आयोग[37] ने न्यायिक सेवा परीक्षा में अंकों के मॉडरेशन के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए। "स्केलिंग" की तुलना में "मॉडरेशन" की विधि को प्राथमिकता देते हुए, यह नोट किया गया कि परीक्षकों की परिवर्तनशीलता को कम करने के लिए मॉडरेशन एक अधिक व्यवहार्य तकनीक है।

77. इसी संदर्भ में, निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी होगा। प्रणव वर्मा और ओआरएस. वी.उच्च न्यायालय के महापंजीयक पंजाब और हरियाणा[38] जहाँ इस न्यायालय ने पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करने के लिए अंकों के मॉडरेशन या सामान्यीकरण का उपयोग करने के विकल्प को रेखांकित किया। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) को नियुक्त किया था। ए. के. सीकरी, सुप्रीम कोर्ट

के एक पूर्व न्यायाधीश, एक भर्ती अभ्यास में चयन प्रक्रिया की जांच करने के लिए जहां पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार योग्य नहीं थे। विद्वान न्यायाधीश ने चयन प्रक्रिया को सत्यापित किया लेकिन कोई बुनियादी खामियां नहीं पाईं। हालांकि, सिविल लॉ-I के पेपर के मूल्यांकन में कमियां पाई गईं क्योंकि उम्मीदवारों के पास जवाब देने के लिए प्रत्येक प्रश्न केवल 8.5 मिनट उपलब्ध थे यह वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्नों और लंबे पेपर के लिए अपर्याप्त माना गया था। यह भी देखा गया कि सिविल लॉ-II के पेपर में अंकन बहुत सख्त था, जिसमें उच्चतम अंक 200 में से 95 (47.5%) थे और मूल्यांकनकर्ता, जैसा कि देखा जा सकता है, उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध सीमित समय पर विचार किए बिना प्रत्येक प्रश्न के लिए लंबे उत्तरों की अपेक्षा करते थे। इन तथ्यों पर ध्यान देने के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चयन प्रक्रिया को अमान्य करने की आवश्यकता नहीं है। चयन को बचाने के बजाय, न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी परीक्षार्थियों को अनुग्रह अंक दिए जाएं।

78. उपरोक्त से पता चलता है कि यदि चयन प्रक्रिया में कुछ हल करने योग्य कमियां देखी जाती हैं, तो उच्च न्यायालय के पास सुधारात्मक उपाय करने की गुंजाइश है। मोडरेशन की प्रक्रिया का प्रयोग हमेशा ईमानदारी से किया जा सकता है यदि यह सभी उम्मीदवारों को समान रूप से लाभान्वित करता है। इस संदर्भ में, उच्च न्यायालय के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत चार्ट से यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में, मध्यस्थता से वर्तमान रिट याचिकाकर्ताओं को साक्षात्कार दौर में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए लाभ हुआ। बिहार नियम 1951 के परिशिष्ट-'सी' के खंड 10 के प्रावधान से कुल अंकों में 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की कमी का पता लगाया जा सकता है। आर. टी. आई. जवाब में वर्णित घटनाओं के क्रम में मामूली भिन्नता दिखाई गई है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी अतिरिक्त हलफनामे से यह स्पष्ट होता है कि

मोडरेशन अभ्यास के बाद, नियमों के अनुसार कुल अंक घटाकर 50 प्रतिशत कर दिए गए थे।

79. यह तर्क कि साक्षात्कार के लिए भी योग्यता अंकों को लिखित परीक्षा की तरह ही कम किया जाना चाहिए था, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमों में ही लिखित परीक्षा में कुल अंकों में कमी का प्रावधान किया गया है। छूट से संबंधित प्रावधान खंड 10 में निहित है जो केवल लिखित परीक्षा से संबंधित है। न्यायालय को किसी भी मामले में चयन समिति के दायरे में नहीं आना चाहिए। चयन समिति/साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का मूल्यांकन और मूल्यांकन समिति के सदस्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए जब तक कि यह वैधानिक नियमों का उल्लंघन न करे या गलत उद्देश्य से दूषित न हो। चयन समिति के निर्णय को पूर्ण न्यायालय द्वारा अंतिम चयन के लिए उपलब्ध उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने के लिए मंजूरी दी गई थी।

80. परीक्षा आयोजित करने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए बाद के कदमों की जांच करने पर, हम बिहार में पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित करने के लिए कोई दुर्भावनापूर्ण या वैधानिक उल्लंघन नहीं पाते हैं। इसी तरह गुजरात के मामलों में अस्पष्ट आरोप लगाने के अलावा याचिकाकर्ताओं ने साक्षात्कार प्रक्रिया में चयन समिति की ओर से किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे या पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई। अतः चयन प्रक्रिया दूषित नहीं पाई जाती है। मुद्दा संख्या iv) क्या संविधान के अनुच्छेद 234 के तहत न्यूनतम वाइवा वॉस अंक निर्धारित करने वाले चयन नियमों में संशोधन के लिए लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श न करना अमान्य हो जाता है?

81. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री पवनश्री अग्रवाल ने तर्क दिया है कि 2021 के डब्ल्यू. पी. (सी) 663 में 2022 के आई. ए. 20279 में अनुच्छेद 234 के उल्लंघन के

कारण एक अतिरिक्त चुनौती दी गई है। यह तर्क दिया जाता है कि 2011 में संशोधित नियम 8 (3) के तहत वाइवा-वॉयस में न्यूनतम योग्यता अंकों का निर्धारण केवल गुजरात उच्च न्यायालय के परामर्श से था, लेकिन गुजरात लोक सेवा आयोग के परामर्श से नहीं। इसलिए, अनुच्छेद 234 की अनिवार्य आवश्यकता को देखते हुए, नियमों को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, गुजरात उच्च न्यायालय की ओर से श्री मलकान ने तर्क दिया कि लोक सेवा आयोग ने स्वयं अनुरोध किया था कि गुजरात लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1960 के अनुसार छूट भारत के संविधान का अनुच्छेद 320 (3)। इसके अतिरिक्त, सुश्री दीपानविता प्रियंका, जो गुजरात राज्य के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुईं, ने गुजरात लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांकित एक पत्र की सामग्री पढ़ी, जिसमें कहा गया था कि "सिविल जज" का प्रस्तावित पद इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

82. उपरोक्त तर्कों की सराहना करने के लिए, 2011 के संशोधन से पहले गुजरात नियम, 2005 के प्रासंगिक भाग पर ध्यान देना उपयोगी होगाः

> “भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात के राज्यपाल, गुजरात उच्च न्यायालय और गुजरात लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करने के बाद, और गुजरात न्यायिक सेवा भर्ती नियम, 1961 के स्थान पर, गुजरात राज्य न्यायिक सेवा में भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं। ”

83. गुजरात नियम, 2005 (2011 में संशोधित) के प्रासंगिक भाग को आगे निकाला गया हैः

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद ए के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात के राज्यपाल ने गुजरात उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं। "

84. 2011 के नियमों में "और गुजरात लोक सेवा आयोग" शब्दों को छोड़ना एक प्रासंगिक पहलू है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 234 और 235 जो "अधीनस्थ न्यायालयों" से संबंधित हैं, उन पर यहां विचार किया जाएगा। अनुच्छेद 233 लोक सेवा आयोग के परामर्श की आवश्यकता के बिना जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 234 राज्य के राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद नियमों के अनुसार राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 234 हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैः

"किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करने के बाद उस ओर से बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी।

85. चूंकि नियम अनुच्छेद 309 के प्रावधान के अनुसार बनाए गए थे, इसलिए इसे तैयार संदर्भ के लिए नीचे भी निकाला गया हैः

"309. संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें

इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, उपयुक्त विधानमंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित कर सकते हैं। बशर्ते कि यह राष्ट्रपति या ऐसे व्यक्ति के लिए सक्षम होगा जिसे वह संघ के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों के मामले में निर्देश दे, और किसी राज्य के राज्यपाल के लिए या जिस व्यक्ति को वह राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों के मामले में ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने का निर्देश दे सकता है, जब तक कि इस अनुच्छेद के तहत उपयुक्त विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा या उसके तहत उस ओर से प्रावधान नहीं किया जाता है, और इस तरह बनाए गए कोई भी नियम ऐसे किसी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। ”

86. इस न्यायालय को कई निर्णयों में अनुच्छेदों में उपरोक्त प्रावधानों की जांच करने का अवसर मिला है। हालांकि यह सच है कि अनुच्छेद 234 लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के साथ परामर्श को अनिवार्य करता है, इस न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद साह[39] (संक्षेप में "बाल मुकुंद"), कि दोनों के बीच परामर्श की प्रकृति में एक अच्छा अंतर हैः

“51. जैसा कि पहले देखा गया है, अनुच्छेद 234 द्वारा परिकल्पित उच्च न्यायालय के साथ परामर्श न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के संवैधानिक जनादेश को सफल बनाने के लिए है, जो इसकी मूल संरचना है। लोक सेवा आयोग की ऐसी कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। जाँच निकाय के परामर्श के दायरे को कभी भी नियुक्ति निकाय के साथ परामर्श के दायरे के बराबर नहीं माना जा सकता है जिसका

प्रतिनिधि पूर्व है। यह भी ध्यान रखना उचित है कि परामर्श का सार सलाह देने के लिए एक वास्तविक निमंत्रण का संचार और उस सलाह पर वास्तविक विचार है जो बदले में संबंधित पक्ष को पर्याप्त जानकारी और समय दिए जाने पर निर्भर करता है ताकि वह उपयोगी सलाह दे सके। यह समझना मुश्किल है कि कैसे राज्यपाल को अनुच्छेद 234 के तहत भर्ती के नियमों को लागू करने से पहले लोक सेवा आयोग से परामर्श करते हुए उसी तरह की सलाह लेनी पड़ती है जैसे वह उचित परामर्श पर उच्च न्यायालय से मांगते हैं। परामर्श की प्रक्रिया में लोक सेवा आयोग द्वारा दी जा सकने वाली सलाह अनुच्छेद 320 की संवैधानिक आवश्यकताओं तक ही सीमित रहेगी। वे पूरी तरह से यह उच्च न्यायालय से परामर्श और सलाह लेने की प्रकृति से अलग है, जिसका संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत अधीनस्थ न्यायपालिका पर पूर्ण नियंत्रण है और यह सीधे तौर पर कुशल न्यायिक नियुक्तियों के मसौदे से संबंधित है ताकि चयन प्रक्रिया के माध्यम से जमीनी स्तर पर और जिला न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर उपयुक्त सामग्री उपलब्ध हो सके। अनुच्छेद 235 के साथ पठित अनुच्छेद 234 के तहत उच्च न्यायालय की भूमिका को ध्यान में रखते हुए परामर्श, लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की तुलना में पूरी तरह से अलग आधार पर खड़ा है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 320 द्वारा परिकल्पित पूरी तरह से अलग प्रकार के अपने कार्यों का निर्वहन करना है। ”

87. यह अच्छी तरह से तय है कि अनुच्छेद 234 में परिकल्पित उच्च न्यायालय के साथ परामर्श न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संवैधानिक जनादेश को संरक्षित करने के लिए है जो भारत के संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की तुलना में न्यायिक भर्ती के मामलों में उच्च न्यायालय के साथ परामर्श को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

88. कानून की उपरोक्त समझ के साथ, आइए अब हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 का उल्लेख करें जो नीचे दिया गया हैः

" **लोक सेवा आयोग के कार्य**

(1) संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएँ आयोजित करें।

(2) संघ लोक सेवा आयोग का यह भी कर्तव्य होगा कि यदि दो या दो से अधिक राज्यों द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है, तो वह उन राज्यों को किसी भी सेवा के लिए संयुक्त भर्ती की योजनाओं को तैयार करने और संचालित करने में सहायता करे, जिसके लिए विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है।

(3) संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, जैसा भी मामला हो, से परामर्श किया जाएगा -

क. सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामलों पर;

ख. सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ करने और एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण करने में पालन किए जाने वाले सिद्धांतों पर और ऐसी नियुक्तियों, पदोन्नति या स्थानान्तरण के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर;

ग. भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत सिविल क्षमता में सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों पर, जिसमें ऐसे मामलों से संबंधित स्मारक या याचिकाएं शामिल हैं;

घ. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत में क्राउन के अधीन या किसी भारतीय राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा कर रहे या सेवा कर चुके किसी व्यक्ति द्वारा या उसके संबंध में किए गए किसी दावे पर कि उसके द्वारा अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए या किए जाने का तात्पर्य रखने वाले कार्यों के संबंध में उसके खिलाफ स्थापित कानूनी कार्यवाही का बचाव करने में किए गए किसी भी खर्च का भुगतान भारत की संचित निधि से या, जैसा भी मामला हो, राज्य की संचित निधि से किया जाना चाहिए।

ङ. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के तहत या भारत में क्राउन के तहत या किसी भारतीय राज्य की सरकार के तहत सिविल क्षमता में सेवा करते समय किसी व्यक्ति को लगी चोटों के संबंध में पेंशन देने के किसी भी दावे पर और ऐसे किसी पुरस्कार की राशि के बारे में किसी भी प्रश्न पर,

और यह लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा कि वह उन्हें इस प्रकार निर्दिष्ट किसी भी मामले पर और किसी अन्य मामले पर, जिसे राष्ट्रपति, या, यथास्थिति, राज्य का राज्यपाल, उन्हें निर्दिष्ट करे, सलाह देः

बशर्ते कि राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में और मामलों के संबंध में अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में भी

संघ का और राज्यपाल, किसी राज्य के मामलों के संबंध में अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में, उन मामलों को निर्दिष्ट करते हुए विनियम बना सकते हैं जिनमें या तो आम तौर पर, या किसी विशेष वर्ग के मामले में या किसी विशेष परिस्थिति में, लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

खंड (3) की किसी बात के लिए यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि अनुच्छेद 16 के खंड (4) में निर्दिष्ट कोई प्रावधान जिस तरीके से किया जा सकता है या अनुच्छेद 335 के प्रावधानों को जिस तरीके से प्रभाव दिया जा सकता है, उसके संबंध में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए।

राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा खंड (3) के परंतुक के तहत बनाए गए सभी विनियम, संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष, जितनी जल्दी हो सके, उनके बनाए जाने के बाद कम से कम चौदह दिनों के लिए रखे जाएंगे और ऐसे संशोधनों के अधीन होंगे, चाहे वे निरसन या संशोधन के रूप में हों, जो संसद के दोनों सदन या सदन या राज्य के विधानमंडल के दोनों सदन उस सत्र के दौरान कर सकते हैं जिसमें वे इस तरह रखे गए हैं। ”

[जोर दिया गया]

89. भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 के तहत "लोक सेवा आयोग" के साथ परामर्श के स्रोत का पता संविधान के अनुच्छेद 320 से लगाया जा सकता है जो "लोक सेवा आयोग के कार्यों" से संबंधित है। इस संबंध में, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने भारत के संवैधानिक कानून[40] में परामर्श की प्रकृति पर यह कहा थाः

“उच्च न्यायालय के साथ परामर्श अनिवार्य है। उच्च न्यायालय के साथ परामर्श पर आग्रह स्पष्ट रूप से उस स्रोत की मान्यता के लिए जिम्मेदार है जिस से अपने नियंत्रण में किसी सेवा से संबंधित मामले में सबसे उपयोगी सलाह प्राप्त की जा सकती है। लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता इस कारण से समान रूप से समझ में आती है कि आयोग को अनुच्छेद 320 द्वारा राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया गया है। ”

90. इस न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय को परामर्श की प्रक्रिया में प्रधानता दी जानी चाहिए और इस तरह के परामर्श के बिना बनाए गए नियम अमान्य होंगे। हालाँकि, लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श के अभाव के लिए यह सच नहीं है। यू. पी. राज्य बनाममनबोधन लाल श्रीवास्तव[42], इस न्यायालय के दौरान संविधान के अनुच्छेद 320 (3) की व्याख्या करते हुए कहा गया था कि "होगा" शब्द को हालांकि आम तौर पर अनिवार्य अर्थों में लिया जाता है, लेकिन इसकी व्याख्या "हो सकता है" के रूप में की जानी चाहिए, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुच्छेद 320 (3) के तहत परामर्श अनिवार्य नहीं है। राजेन्द्र सिंह में भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति का पता लगाना। वर्मा बनाम उपराज्यपाल (एन. सी. टी. दिल्ली)[43], अनिवार्य के संदर्भ में सेवानिवृत्ति के बाद, न्यायालय ने विशेष रूप से उल्लेख किया किः“

> “36. राज्यपाल इस मामले में लोक सेवा आयोग की सलाह पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकते थे। न्यायिक अधिकारियों के मामले में सलाह उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण की नहीं होनी चाहिए। यह अनुच्छेद 235 का स्पष्ट निहितार्थ है। जहाँ तक उच्च न्यायालय का संबंध न्यायिक अधिकारियों से है, अनुच्छेद 320 (3) (सी) पूरी तरह से अनुचित है। अनुच्छेद 320 (3) (सी) की कोई अन्य व्याख्या करना संविधान के अनुच्छेद 235 में अंतर्निहित सर्वोच्च उद्देश्य को विफल करना होगा जिसका उद्देश्य विशेष रूप से न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा और अनिवार्य रूप से अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्यपाल न्यायिक अधिकारियों के मामले में लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं कर सकते हैं और उसकी सलाह स्वीकार कर सकते हैं और उसके अनुसार कार्य

नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल और उच्च न्यायालय के बीच किसी भी बाहरी निकाय के लिए कोई जगह नहीं है। ”

91. इस स्तर पर, यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि इस न्यायालय को यह आधिकारिक रूप से तय करने का काम नहीं सौंपा गया है कि क्या लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 के तहत "अनिवार्य" या "निर्देशिका" होना चाहिए। इन मामलों में जिस प्रश्न का उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि यदि लोक सेवा आयोग स्वयं परामर्श नहीं लेना चाहता है तो क्या नियमों को अमान्य कर दिया जाएगा?लोक सेवा आयोग के संयुक्त सचिव द्वारा लिखा गया दिनांकित 10.6.2005 का पत्र प्रासंगिक है और निम्नानुसार निकाला गया हैः- “

महाशय,

ऊपर उल्लिखित विषय के संदर्भ में, अधिसूचना सं। कानूनी विभाग के जी. के.-2005-5-जे. एस. आर.-1982-994-डी, दिनांक 9/05/2005, तत्काल पद की भर्ती के नियम जारी किए गए हैं। आयोग के दिनांकित 6/06/2005 पत्र के विवरण के अनुसरण में, उपरोक्त नियमों के पहले पैराग्राफ की तीसरी पंक्ति से "और जीपीएससी" के प्रावधान को हटाने का अनुरोध किया जाता है। चूंकि भर्ती नियमों के तहत प्रस्तावित पद आयोग के दायरे में नहीं आते हैं, इसलिए उपरोक्त प्रकाशित भर्ती नियमों से उपरोक्त शब्दों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया जाता है। ”

92. गुजरात उच्च न्यायालय के विद्वान वकील ने प्रविष्टि 11 बी 11 बी गुजरात लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1960 की अनुसूची पर भरोसा किया है जो कि संविधान के अनुच्छेद 320 (3) के प्रावधान में "सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट" के पद का उल्लेख है। ”

93. उपरोक्त चर्चा हमें यह कहने के लिए राजी करती है कि यदि आयोग से परामर्श नहीं करना चाहते हैं तो राज्यपाल को लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की कोई बाध्यता नहीं है। इस तरह का पाठ्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 320 (3) के प्रावधान के अनुरूप होगा। इसलिए, संबंधित गुजरात नियमों को इस मामले में अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है।

94. रिट याचिकाकर्ता के लिए, श्री पवनश्री अग्रवाल ने गोवा न्यायिक मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है। ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम गोवा राज्य[44] का तर्क है कि परामर्श लोक सेवा आयोग के साथ अनिवार्य है। हालांकि यह सच है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि परामर्श अनिवार्य है, निर्णय को सावधानीपूर्वक पढ़ने से पता चलेगा कि न्यायालय ने याचिकाकर्ता को इसमें कोई राहत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि यह सरकार और पी. एस. सी. के बीच का मुद्दा था और याचिकाकर्ता किसी भी कार्रवाई का दावा नहीं कर सकता था। उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से निम्नलिखित रूप में उल्लेख कियाः

> "20. हालाँकि, इस विवाद ने हमें लंबे समय तक रोके रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह मानते हुए भी कि कोई परामर्श नहीं किया गया था, क्या याचिकाकर्ता इस याचिका में कोई राहत पाने का हकदार है। परामर्श या गैर-परामर्श लोक सेवा आयोग और सरकार के बीच का मामला है और वह भी नियम बनाने के चरण में। इसलिए, व्यक्तिगत उम्मीदवार इससे बहुत चिंतित नहीं हैं। उनके अधिकार उच्च न्यायालय या लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श या गैर-परामर्श पर निर्भर या निर्धारित नहीं हैं। इसलिए, लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श न करने से याचिकाकर्ता या याचिकाकर्ता संघ के किसी भी सदस्य को इस रिट याचिका को बनाए रखने के लिए कार्रवाई का कोई कारण नहीं मिलेगा। "

95. इसी तरह, के फैसले पर याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा निर्भरता मद्रास उच्च न्यायालय ने एन. देवासाहयम बनाम मद्रास राज्य[45] में परामर्श की अनिवार्य प्रकृति के संबंध में, जिसे बाल मुकुंद (ऊपर) में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया है, गलत पाया गया है। बाल मुकुंद (ऊपर) में, न्यायालय ने एन. देवसहायम (ऊपर) में निष्कर्ष का समर्थन किया, लेकिन निर्णय से यह भी पता चलेगा कि अनुच्छेद 234 की 'अनिवार्य' या 'निर्देशिका' प्रकृति पर कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं है।

96. इसी तरह, ए. सी. थलवाल बनाम एच. पी.[46] के उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी याचिकाकर्ताओं के लिए कोई सहायक नहीं होगा क्योंकि उस मामले में, पूर्व सैनिक (हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1981 को अमान्य घोषित कर दिया गया था। यह संविधान को अधिकार देता है और इसलिए उच्च न्यायालय के साथ परामर्श न करने के संदर्भ में अमान्य है, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 के तहत लोक सेवा आयोग के साथ नहीं। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, न्यायालय ने कहा कि "एक संस्थान के रूप में उच्च न्यायालय को संवैधानिक योजना में जो दर्जा प्राप्त है और उसके पास न्यायिक सेवाओं की विशेषज्ञता और अनुभव है, वह परामर्श की प्रक्रिया में उच्च न्यायालय को प्रधानता का स्थान देने को उचित ठहराता है। " नियम बनाने के लिए उच्च न्यायालय से परामर्श करना निस्संदेह अनिवार्य है और इस तरह के परामर्श के बिना राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित किसी भी नियम को अधिकार से बाहर माना जाता है। इसका कारण न्यायिक सेवा को कार्यकारी प्रभाव से बचाना है जो एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना के संवैधानिक उद्देश्य में निहित है।

97. गुजरात में, जब लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (3) के प्रावधान के तहत परामर्श नहीं लेना चाहता था, तो इस तरह के परामर्श के अभाव में,

यह नहीं माना जा सकता है कि गुजरात नियम, 2005 किसी भी कानूनी या संवैधानिक अयोग्यता से ग्रस्त है, विशेष रूप से जब नियम उच्च न्यायालय के साथ उचित परामर्श के साथ बनाए गए थे।

VII. निष्कर्ष और निर्देश

98. इन मामलों में हमारे अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, मलिक मजहर बनाम यू. पी. लोक सेवा आयोग[47] का संदर्भ करना उचित होगा जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवा परीक्षाओं के संचालन के लिए एक निर्धारित समय-अनुसूची के महत्व पर जोर दिया। इस मामले में परीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए एक निश्चित समय सीमा की आवश्यकता का भी सुझाव दिया गया था। हाल ही में, जिला न्यायपालिका में न्यायिक रिक्तियों पर ध्यान देते हुए, इस न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था और उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को यह रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था कि क्या न्यायिक रिक्तियों को समय पर भरा जाएगा, जैसा कि मलिक मजहर (उपरोक्त) में निर्धारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग[49] की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मलिक मजहर (ऊपर) में भर्ती के लिए समयसीमा निर्धारित करने के फैसले के बावजूद, 25 राज्यों में से केवल 9 राज्यों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर सिविल जज (जज डिवीजन) की भर्ती पूरी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार राज्य को विज्ञापन की तारीख (9 मार्च, 2020) से अंतिम परिणाम की तारीख (10 अक्टूबर, 2022) तक गणना की गई भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में 945 दिन लगे।

99. जैसा कि हमारे सामने मामलों में भी देखा जा सकता है, बिहार चयन प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जनवरी, 2015 में जारी किया गया था; अंतिम चयन 17.5.2016 पर किया गया था, और कुछ पाठ्यक्रम सुधार करने की आवश्यकता के कारण, अंतिम उम्मीदवार को केवल अगस्त, 2016 में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। इसी तरह, गुजरात

में सिविल न्यायाधीशों के चयन के लिए, जबकि विज्ञापन 2019 में जारी किया गया था, चयन प्रक्रिया केवल 2021 में पूरी की जा सकी।

100. बिहार राज्य में भर्ती में दिखाई देने वाली भटकती प्रक्रिया से बचने और प्रक्रिया के साथ अधिक स्पष्टता और निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए, हम यह घोषणा करना आवश्यक समझते हैं कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने और चयन प्रक्रिया में दुविधाओं से बचने के लिए नियमों में मोडरेशन जैसी प्रक्रियाओं को अधिमानतः निर्धारित किया जाना चाहिए। साक्षात्कार खंड में विचार के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, जब प्राधिकरण को ऐसा करने की आवश्यकता हो, तो वास्तविक कारणों के लिए अंकों के मॉडरेशन की अनुमति दी जानी चाहिए। विश्वास निर्माण के उपाय के रूप में, साक्षात्कार पैनल में उन लोगों का पदनाम भी नियमों में उचित रूप से प्रदान किया जा सकता है। इस स्तर पर 29 राज्यों के न्यायिक सेवा नियमों की जांच करने वाली "विवेकाधिकार और विलंब-जिला और सिविल न्यायाधीश बनने की चुनौती"[50] शीर्षक वाली विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की दिसंबर, 2018 की रिपोर्ट में की गई कुछ सिफारिशों पर ध्यान देना उचित होगा। एक निर्दिष्ट प्राधिकारी की अनुपस्थिति जिसे उम्मीदवारों द्वारा संपर्क किया जा सकता है, उक्त रिपोर्ट में चिह्नित किया गया है। चूंकि यह एक वैध चिंता प्रतीत होती है, संबंधित उच्च न्यायालय को स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं, कार्यों और जिम्मेदारियों के साथ दी गई भर्ती प्रक्रिया के लिए एक नामित प्राधिकरण को अधिसूचित करना चाहिए। उम्मीदवार किसी भी संदेह के मामले में स्पष्टीकरण लेने के लिए ऐसे नामित प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और इससे उम्मीदवारों की चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी। प्रस्तावित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम की एक बुनियादी रूपरेखा प्रदान करने के इस तरह के एक अन्य सुझाव से विभिन्न पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को परीक्षा अधिसूचना जारी होने से पहले ही प्रस्तावित परीक्षा की योजना

बनाने और तैयारी करने में मदद मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया को समय-सीमा का पालन करना चाहिए लेकिन यदि कोई विशेष और अपरिहार्य आवश्यकता है, तो हितधारकों को उचित शीघ्रता के साथ सूचित किया जाना चाहिए।

101. उपरोक्त निर्देशों के अनुसार सभी हितधारकों को परिणामी कदम उठाने में सक्षम बनाने के लिए, इस निर्णय को भारत के सभी उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायाधीशों के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

102. पूर्वगामी चर्चा के साथ, विचाराधीन मामलों के लिए निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैंः-

i) साक्षात्कार के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों का निर्धारण अनुमत है और यह अखिल भारतीय न्यायाधीशों (2002) का उल्लंघन नहीं है जिसने शेट्टी आयोग की कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया था।

ii) बिहार नियम, 1951 के खंड 11 और गुजरात नियम, 2005 (2011 में संशोधित) के नियम 8 (3) को चुनौती दी गई है, जिसमें साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं को बरकरार रखा जाता है।

iii) बिहार और गुजरात राज्य में विवादित चयन प्रक्रिया को कानूनी रूप से वैध पाया जाता है और इसे बरकरार रखा जाता है।

iv) लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श न करने से गुजरात नियम, 2005 (2011 में संशोधित) अमान्य नहीं हो जाएगा। तदनुसार, रिट याचिकाओं को लागत पर किसी भी आदेश के बिना खारिज किया जाता है।

मामले का परिणामःलिखित याचिकाएँ खारिज की जाती है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटःनिधि जैन

* लेखक

1 [2002] 2 एस. सी. आर. 712 : (2002) 4 एस. सी. सी. 247

2 राज कुमार बनाम शक्ति राज (1997) 9 एससीसी 527

3 बशेशर नाथ बनाम कम्र। आय-कर, दिल्ली, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 149; ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, ए. आई. आर. 1986 एस. सी. 180; नर सिंह पाल बनाम भारत संघ और अन्य, 2000 3 एस. सी. सी. 588।

4 मदन लाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1995) 3 एस. सी. सी. 486; धनंजय मलिक बनाम उत्तरांचल राज्य (2008) 4 एस. सी. सी. 171; रमेश चंद्र शाह बनाम अनिल जोशी (2013) 11 एस. सी. सी. 309; अनुपल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020) 2 एस. सी. सी. 173

5 कृष्ण राय बनाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (2022) 8 एससीसी 713 6 (2019) 20 एससीसी 17 552

6 (2019) 20 एस. सी. सी. 17

7 [1962] 1 एससीआर 574:ए. आई. आर 1961 एस. सी 1457

8 इंदरजीत सिंह सोढ़ी बनाम अध्यक्ष, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (2021) 1 एस. सी. सी. 198।

9 [1991] पूरक। 2 एससीआर 206:(1992) 1 एससीसी 119 [2024] 6 एस. सी. आर.

10 [1993] सप.1 एससीआर 749:(1993) 4 एससीसी 288 554

11 प्रदीप कुमार राय बनाम दिनेश कुमार पांडे (2015) 11 एस. सी. सी. 493 (पैरा 17)

12 [2024] 2 एससीआर 1136:2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 254

13 [2003] सप.1 एससीआर 114:(2003) 9 एससीसी 592

14 [2010] 2 एससीआर 239:(2010) 2 एससीसी 637 [2024] 6 एस. सी. आर.

15 [2013] 13 एससीआर 884:(2013) 11 एस. सी. सी. 87 562

16 [2013] 12 एससीआर 985:(2014) 2 एससीसी 158 [2024] 6 एस. सी. आर.

17 डॉ. कविता खंबा बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 254

18 शिवानंद सीटी बनाम केरल उच्च न्यायालय (2024) 3 एससीसी 799

19 [2008] 5 एससीआर 1066:(2008) 7 एससीसी 11

20 [2010] 2 एससीआर 256:(2010) 3 एससीसी 104 564

21 तेज प्रकाश पाठक और ओआरएस. वी.राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य। सी. ए. सं. 2634/2013 और बैच 566

22 [2016] 9 एससीआर 771:(2016) 10 एस. सी. सी. 484 [2024] 6 एस. सी. आर.

23 शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 (9) एस. सी. सी. 1; जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2019) 3 एस. सी. सी. 39; लोक प्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (पैरा 30,35,36,39) (2016) 8 एस. सी. सी. 389

24 [1974] 2 एस. सी. आर. 328:(1974) 4 एससीसी 3 568

25 [1981] 2 एससीआर 79:(1981) 1 एससीसी 722 [2024] 6 एस. सी. आर.

26 [2017] 9 एससीआर 797:2017 (9) एससीसी 1

27 एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ, 2024 आई. एन. एस. सी. 113; जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ 2019 (3) एस. सी. सी. 39; लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2018 (6) एस. सी. सी. 1; शायरा बानो बनाम भारत संघ, 2017 (9) एस सी सी 1

28 [1982] 1 एससीआर 320:(1981) 4 एससीसी 159

29 के. एच. सिराज बनाम केरल उच्च न्यायालय (2006) 6 एस. सी. सी. 395; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रफीक्विद्दीन, 1987 पूरक एस. सी. सी. 410; तानिया मलिक बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक (2018) 14 एस. सी. सी. 129; प्रणव वर्मा बनाम उच्च न्यायालय के महापंजीयक (2020) 15 एस. सी. सी. 377

30 (2018) 14 एस. सी. सी 129 [2024] 6 एस. सी. आर.

31 [2017] 1 एससीआर 631:(2019) 16 एस. सी. सी 129

32 माइकल जे. सैंडल, द टायरेनी ऑफ मेरिटःआम भलाई का क्या हुआ है?(एलन लेन, 2020) [2024] 6 एस सी आर।

33 मनीष कुमार शाही बनाम बिहार राज्य (2010) 12 एससीसी 576 576

34 [2023] 11 एससीआर 674:(2024) 3 एससीसी 799 [2024] 6 एस. सी. आर.

35 के. एच. सिराज बनाम केरल उच्च न्यायालय (2006) 6 एससीसी 395; इंदरप्रीत सिंह काहलों बनाम पंजाब राज्य (2006) 11 एस. सी. सी. 356

36 [1985] सप.1 एससीआर 657:(1985) 4 एससीसी 417 578

37 [2007] 1 एससीआर 235:(2007) 3 एससीसी 720

38 [2019] 15 एससीआर 43:(2020) 15 एस. सी. सी. 377 [2024] 6 एस. सी. आर.

39 [2000] 2 एससीआर 299:(2000) 4 एससीसी 640 [2024] 6 एस. सी. आर.

40 एम. हिदायतुल्ला (एड), भारत का संवैधानिक कानून (द बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट, अर्नोल्ड-हेनेमैन पब्लिशर्स, 1984 के सहयोग से) खंड। 2, 147

41 ए. सी. थलवाल बनाम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (2000) 7 एस. सी. सी. 1; सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1993) 4 एस. सी. सी. 441; हरि दत्त कैंथला बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, 1980 3 एस. सी. सी. 189

42 [1958] 1 एससीआर 533:ए. आई. आर 1957 एस. सी. 912

43 [2011] 12 एससीआर 496:(2011) 10 एससीसी 1

44 1997(4) BOM CR 372 590

45 ए. आई. आर. 1958 मैड 53

46 [2000] सप.2 एससीआर 428: (2000) 7 एससीसी 1

47 [2006] 3 एससीआर 689:(2006) 9 एससीसी 507

48 रिक्तियों को भरना, 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 3648

49 अनुसंधान और योजना केंद्र, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका राज्य, पर एक रिपोर्ट अवसंरचना, बजट, मानव संसाधन और आई. सी. टी. (नवंबर 2023)

50 दीक्षा सान्याल और श्रीयम गुप्ता, "विवेक और विलम्बःजिला और सिविल न्यायाधीश बनने की चुनौती "(दिसंबर 2018) <https://vidhilegalpolicy.in/research/2019-1-7-discretion-and-delaychallenges-of-becoming-a-district-and-civil-judge/> 03 मई 2024 को एक्सेस किया गया

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।